● वर्ष-3
● अंक-300
रायपुर, रविवार
28 जुलाई 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› उत्तर भारत में खरीफ मौसम...

छत्तीसगढ़ में स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा

राज्य की जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य - साय

नीति आयोग की बैठक मे शामिल हुए मुख्यमंत्री

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास , स्वास्थ्य, और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि , छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। वर्तमान में राज्य का जीडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी क्षमताएँ देना है जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड (APAAR आईडी) बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मौजूद होंगी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास, और राज्य की संस्कृति व परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और 100 गांवों को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना बनाई है। सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है, और नया रायपुर के अधिकांश सरकारी भवनों में ये संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं, जिनसे विद्युत आपूर्ति ग्रिड में की जाती है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक केवल विकसित ही नहीं, बल्कि जल-सुरक्षित भारत 2047 भी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से तकनीकी और आर्थिक सहयोग की उम्मीद जताई इसके अलावा, रायपुर में नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को और मजबूत करने के साथ-साथ वर्षा-जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भी मांग की। उन्होंने कहा कि, इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ में बारिश के पानी को सही से संचित और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जल संकट कम होगा और किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है। अब छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। इन मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री साय ने भूमि और संपत्ति के मुद्दों पर कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। उन्होंने बताया कि इस सुधार से भूमि विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा, जिससे राज्य में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के प्रति समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मौके पर समस्त केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य व छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन उपस्थित रहे।

10 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए

नई दिल्ली। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासनिक परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 10 अनुपस्थित और 26 प्रतिभागी थे। हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुदुचेरी से अनुपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौजूद रहीं। बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दोपहर के भोजन से पहले बारी देने का अनुरोध किया था। मैं सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं, कोई व्याख्या नहीं। यह उनकी ओर से बहुत स्पष्ट अनुरोध था क्योंकि आम तौर पर हम वर्णानुक्रम में जाते। तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से। उन्होंने कहा कि हमने वास्तव में समायोजन किया और रक्षा मंत्री ने वास्तव में उन्हें गुजरात से ठीक पहले बुलाया। तो उसने अपना बयान दिया। प्रत्येक मुख्यमंत्री को सात मिनट आवंटित किए जाते हैं और स्क्रीन के शीर्ष पर बस एक घड़ी होती है जो आपको शेष समय बताती है। उन्होंने अपनी बातें रखीं और हमने सम्मानपूर्वक उन बिंदुओं को सुना और नोट किया, जो एक मिनट में प्रतिबिंबित होंगे। उन्होंने कहा कि केवल इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए कि मुख्य सचिव उपस्थित रहे और उनके जाने के बाद भी वह कमरे में थे क्योंकि उन्हें कलकत्ता के लिए उड़ान पकड़नी थी।

भाजपा मुख्यमंत्रियों की बैठक में हाईकमान का फरमान

शक्ति प्रदर्शन और बयानबाजी से आएं बाज

नई दिल्ली। यूपी भाजपा में मचे घमासान को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकमान ने पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों को सार्वजनिक बयानबाजी और शक्तिप्रदर्शन जैसी स्थिति पैदा करने से बाज आने का फरमान भी सुनाया है। पार्टी हाईकमान की ओर से सभी नेताओं से यह भी कहा गया है कि मनभेद और मतभेद का सार्वजनिक प्रदर्शन करने की आदत पर लगाम लगाएं। सभी मंत्री अपने-अपने काम काज पर ध्यान दें, किसी दूसरे के कामकाज में दखलअंदाजी न करें। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में बुलाई गई दो दिवसीय मुख्यमंत्री की बैठक शुरू होने से पहले उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। दोनों नेताओं की अमित शाह से मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पहले अमित शाह ने दोनों डिप्टी से सीएम से बात की। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूद में यूपी के हालात पर चर्चा हुई है। दोनों डिप्टी सीएम ने अपने-अपने पक्ष रखे। इस पर उन्हें आपस से मिल जुलकर काम करने के साथ ही 10 विधानसभा के लिए होने वाले उप चुनाव में जुटने को कहा गया है। उधर मुख्यमंत्री की आज शीर्ष नेतृत्व के किसी नेता से अकेले में मुलाकात तो नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने यूपी भवन में करीब एक घंटे से तक सीएम योगी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूपी की ताजा सियासी हालात पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि सीएम की भले ही शीर्ष नेतृत्व से अकेले में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बीएल संतोष ने सीएम के साथ हुई बातचीत का ब्योरा शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है। इसके बाद ही हाईकमान ने सभी नेताओं को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री रविवार को सुबह पीएम नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि शनिवार को नीति आयोग और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम की मुलाकात तो तीनों नेताओं से हुई है, लेकिन यूपी के संदर्भ में बातचीत के लिए योगी रविवार को तीनों से नेताओं से मिल सकते हैं।

रायपुर। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ के जैवलिन थ्रो के 16 वर्षीय खिलाड़ी विजय यादव की तारीफ की और ओलंपियन श्री नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेने कहा। उन्होंने श्री यादव को शाबासी देते हुए कहा कि इतने कम उम्र में यह उम्दा प्रदर्शन है। सरगुजा जिले के इस खिलाड़ी ने 68 मीटर से अधिक की लंबी दूरी तक भाला फेंककर अपना दम दिखाया। (विस्तृत समाचार पेज 3 पर)

प्रमुख समाचार

बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का जीत से आगाज

पेरिस। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। पहले ग्रुप मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन के खिलाफ खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। पहला गेम महज 14 मिनट में जीतने के बाद दूसरे गेम में पीछे होने के बाद वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। लक्ष्य ने ग्वाटेमाला के खिलाड़ी को खिलाफ मैच 21-8 और 22-20 से जीता। लक्ष्य से ने पेरिस ओलंपिक की शुरुआत अपने ही अंदाज में जीत के साथ की है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी से देश को पदक की उम्मीद है। पहले ग्रुप मुकाबले में इस खिलाड़ी का सामना ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन के खिलाफ था। आक्रामक शुरुआत करते हुए लक्ष्य ने पहले गेम में महज 14 मिनट में खत्म कर दिया। 21-8 के बड़े अंतर से गेम को एकतरफा बनाते हुए बढ़त हासिल की।

ओडिशा से दो हजार बीएसएफ कर्मी भेजे गए जम्मू

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय की तरफ से बीएसएफ को इस सप्ताह की शुरुआत में एक आदेश मिला है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओडिशा से दो हजार बीएसएफ कर्मियों को जम्मू क्षेत्र में भेजने का फैसला लिया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा को मजबूत करना और बढ़ते खतरों का मुकाबला करना है। यह निर्णय जम्मू क्षेत्र में हाल ही में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों के बाद लिया गया है, जिसने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। ओडिशा में अब तक ये दोनों बटालियन नक्सल विरोधी अभियानों में लगी हुई थीं और अब वे आतंकवाद से प्रभावित जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करेंगी। सूत्रों के अनुसार, इन बलों की तैनाती से सरकार का इरादा आतंकी गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करना, क्षेत्र और इसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 21 जुलाई को जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों की परिचालन तैयारियों का जायजा लिया था।

झारखंड में 45 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये फटाफट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान खूब देखने सुनने को मिले। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार केक दौरान खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने गरीबों के खाते में एक-एक लाख रुपये डालकर खटाखट गरीबी खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी न सत्ता में आए और नही गरीबी खत्म करने के दावे के साथ एक एक लाख रुपये अकाउंट में आने की बात सच हो पाई। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इससे संबंधित एक फैसला लिया है जिससे हर महीने 45 लाख महिलाओं के एकाउंट में 1000 रुपये टकाटक जरूर आने लग जाएंगे। दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सोरेन सरकार ने 30 एजेंडों पर मुहर लगी। 21-50 साल की महिलाओं को हर महीने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संशोधन को स्वीकृति दी गई है और इसके तहत 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। 'मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना' के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

ममता के समर्थन में उतरे एमके स्टालिन

नई दिल्ली। एमके स्टालिन ने आगे साफ तौर पर कहा कि सहकारी संघवाद के लिए सभी आवाजों के लिए संवाद और सम्मान की आवश्यकता है। दिल्ली में बनर्जी ने दावा किया कि उनका माइक्रोफोन सिर्फ पांच मिनट के बाद काट दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए अधिक समय दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के बाद केंद्र सरकार की आलोचना की कि नीति आयोग की बैठक में उनके भाषण के दौरान उन्हें अनुचित तरीके से रोका गया था। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में स्टालिन ने सवाल किया, क्या यह सहकारी संघवाद है? क्या एक मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है? केंद्र की भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि विपक्षी दल हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और उन्हें चुप कराने के लिए दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। एमके स्टालिन ने आगे साफ तौर पर कहा कि सहकारी संघवाद के लिए सभी आवाजों के लिए संवाद और सम्मान की आवश्यकता है।

गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ धमकाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस सांसद ने अपने पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की और उम्मीद जताई कि वह संसद सदस्यों के खिलाफ निंदनीय बयान देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। गौरव गोगोई ने पत्र में कहा कि मैं आपको लोकसभा में संसदीय आचरण के गिरते मानकों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जैसा कि चल रहे मानसून सत्र के कई उदाहरणों से स्पष्ट है। अक्सर, सरकार के मंत्री ही विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ असंसदीय, आपत्तिजनक और धमकाने वाली टिप्पणियां करते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया, जो संसद के सदस्य नहीं हैं। इस कड़ी में गोगोई ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया।

क्लिंटन के रूख से क्यों रह गए हैरान?

एलओसी पार करने की तैयारी में था भारत, भागे-भागे अमेरिका पहुंचे नवाज

अभिनय आकाश

26 जुलाई यह महज एक तारीख नहीं यह दिन है याद दिलाने के लिए कि देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुर्बानी क्या होती है। यह दिन है उन तमाम रणबांकुरे के आगे नमन करने का जो अपने आप को वर्दी में बांधकर देश को सुरक्षित फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यह दिन है उन तमाम साहसी जवानों के आगे झुककर नतमस्तक हो जाने का जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए अग्रसर होते हैं। वह है वतन, देश, हिंदुस्तान हमारा, इंडिया, हमारा भारत। आज कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लेने की ठान ली थी। आलम ये हो गया था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आनन-फानन में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मदद की गुहार लगानी पड़ी थी।

कोई भी उस कूटनीतिक परिदृश्य की गंभीरता की कल्पना कर सकता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कारगिल युद्ध के दौरान निपट रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने शरीफ को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान को अपनी सेना वहां से हटाने के लिए साफ कह दिया था। यही कारण है कि बिल क्लिंटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन किया था। वरना आपने 1971 के दौर में तो भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा तक भेज दिया था। क्लिंटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर गुस्से में चर्चा कर रहे थे। क्लिंटन शरीफ के साथ बातचीत के दौरान आपा खो बैठे थे, जो उन परिस्थितियों के बारे में अनभिज्ञता का दावा कर रहे थे जिनके तहत पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल दुस्साहस शुरू किया था। यह संभवत: सबसे चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक कार्य था जिसका किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब सामना किया जब उनका देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसके बावजूद हालात की गंभीरता को देखते हुए क्लिंटन ने वाइट हाउस में नवाज शरीफ के साथ इसी दिन बैठक की और उन्हें पीछे हटने के लिए राजी किया।

दो दक्षिण एशियाई शक्तियों के बीच परमाणु संघर्ष की संभावना के बारे में गहराई से चिंतित, संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल क्लिंटन प्रशासन तेजी से संकट में मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ा। तत्कालीन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) के विश्लेषक ब्रूस रीडेल युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निकट पूर्वी और दक्षिण एशिया मामलों के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन के विशेष सहायक थे। बाद में उन्होंने विस्तार से लिखा और बताया कि क्लिंटन ने संकट से कैसे निपटा, जबकि रिडेल ने खुद को इन महत्वपूर्ण राजनयिक प्रयासों के केंद्र में पाया। क्लिंटन की टीम में उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टैलबोट और जनरल टोनी ज़िन्नी जैसे लोग भी शामिल थे, जो पाकिस्तान से एलओसी के पीछे अपनी सेना वापस बुलाने का आग्रह करने में अथक प्रयास कर रहे थे। अमेरिका के इस नए रुख ने भारत और पाकिस्तान दोनों को चौंका दिया क्योंकि इस्लामाबाद ने सोचा था कि अमेरिका हमेशा की तरह उसका साथ देगा और भारत को गुण दोष के आधार पर फैसले किए जाने की तो अमेरिका से उस वक्त उम्मीद ही नहीं थी।

क्लिंटन ने खुफिया सूचनाओं और अटकलों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका जताई थी कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार तैनात किए तो भारत पूरी ताकत से जवाब देगा, वहीं वाजपेयी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी पीएम शरीफ के बीच अगली बैठक के लिए माहौल तैयार कर दिया। पत्रकार बरखा दत्त अपनी किताब %द अनक्राइट लैंड - स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज फॉल्ट लाइन्स% के अनुसार भारतीय सेना के पास 'छह दिवसीय युद्ध' की आकस्मिक योजना थी,जिसमें सैनिकों को इस तरह से तैनात करने की योजना थी कि यदि आवश्यक हुआ तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा को एक सप्ताह से भी कम समय में पार किया जा सके। रीडेल ने 2002 में इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में लिखा था कि वह कॉल 2 जुलाई को हुई थी।

उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ने फोन पर भारतीय प्रधान मंत्री वाजपेयी से सलाह ली। भारतीय अड़े हुए थे - एलओसी पर वापसी जरूरी थी, आक्रामकता की धमकी के तहत वाजपेयी बातचीत नहीं करेंगे। जब क्लिंटन ने वाजपेयी को फोन करके वादा किया कि अमेरिका पाकिस्तान पर भारतीय क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए काम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री चुप रहे। साठ दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कारगिल में हिंद के शूरवीरों के प्रचंड पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

करगिल की चोटियों से बेदखल करने के लिए भारतीय सेना के 527 वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज प्राडेय, अजया आहूजा जैसे वीरों की कुर्बानियां निसिया बीरगाथाओं में शुमार हो चुकी है। निश्चय ही पाकिस्तानी सेना करगिल में फंस चुकी थी और नवाज शरीफ को चेहरा छुपाने के लिए अमेरिकी बीच बचाव का बहाना चाहिए था।

बलौदाबाजार में बारिश में बह गया सिस्टम, दूसरे जिलों से संपर्क टूटा

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में लगातार बारिश से हालात खराब हैं। भाटापारा में जनपद पंचायत कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, ग्रामीण थाना, बलौदाबाजार जाने वाली कई सड़क करीब एक किलोमीटर तक पानी से डुबी हुई है।

बच्चे सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों के सामने खेल रहे हैं। बलौदाबाजार से बिलासपुर, बेमेतरा, मुंगेली, अकलतरा, रायपुर मार्ग प्रभावित है। इन सभी जगह से संपर्क टूट गया है- थाना-भाटापारा ग्रामीण सेमरिया घाट पुल से आवागमन बंद। थाना -गिधपुरी अमेठी घाट पुल से आवाजाही बंद। थाना- सिमगा ग्राम गणेशपुर में भरा पानी। कोनी घाट, पनपुरवा घाट, सिल्वा घाट बंद। थाना- सुहेला झीपन नाला बंद। थाना -हथबंद भंवरगढ़ नाला बंद।

भाटापारा नगर पालिका को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन बारिश ने शहर की पानी निकासी की व्यवस्था की पोल खोल दी है। सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है।

तमाम सरकारी कार्यालय, स्कूलों और पंचायत भवनों में पानी घुस चुका है। पलारी बिजली विभाग, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी कार्यालय परिसर में पानी भरा हुआ है। करीब तीन से चार फीट पानी भर चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाने से मरीजों की मुश्किल बढ़ गई है। बलौदाबाजार में डायरिया से एक महिला की मौत भी हो चुकी है।

भाटापारा में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है। लोग अब पंप की मदद से अपने घरों में घुसे पानी को बाहर निकाल रहे हैं।

बलौदाबाजार और भाटापारा दोनों को जोड़ कर बलौदाबाजार भाटापारा जिला बनाया गया है। जिला बने 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरे।

पार्षद ने बताया कि वार्ड 15 में 15 से 20 वार्डों के नाली का पानी आता है। पिछले दो तीन दिन तक लगातार खूब बारिश हुई। बारिश के बाद पानी का बहाव ऐसा हुआ कि भाटापारा शहर में लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोगों के घरों में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। मकान गिरने का खतरा है और जहरीले जंतु आने की भी संभावना रहती है।

भारी बारिश के चलते खेत लबालब हो गए हैं। किसानों को फसल की चिंता सता रही है। बारिश के पानी की निकासी का साधन नहीं होने से बीज पानी में सड़ने की आशंका है।

बलौदाबाजार में गांव में घुसा पानी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश ने अब तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। सिमगा ब्लॉक के देवरीडीह में दरचुरा बांध में ज्यादा दबाव से इसका एक छोर फुट गया है। जलाशय का पानी सड़क मार्ग से खेतों में बहने लग गया है।

जलाशय फूटने की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और लोगों को सतर्क रहने कहा गया है। गनीमत यह रही कि फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। यह जलाशय पचास एकड़ में बना हुआ है। इस जलाशय से आसपास के गांव में खेती के लिए सिंचाई होती है। यहां से भाटापारा के नलों में पानी जाता है।बांध टूटने के बाद जब ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची। अकलतरा रोड पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। करीब 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। अकेले गणेशपुरी में ही 200 से 300 घर डूब गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है की दरचुरा बांध का टूटने का कारण पानी नहीं, बल्कि मछुआरे हैं। यह मछुआरे बांध पर मछली पालने का ठेका लेकर रखे हुए हैं। बांध का गेट खोला नहीं गया था। ना ही नहर में पानी दिया गया था। ठेकेदार ने मनमानी की है।

भाटापारा विधायक इंद्र कुमार साहू ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों ने समय पर सूचना दी थी लेकिन अफसरों ने लापरवाही की है। इंद्र कुमार साहू ने कहा यह बहुत ही दुख का विषय है। इसके जिम्मेदार संबंधित विभाग के आला अधिकारी हैं। गणेशपुरी गांव के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा बांध के ऊपर से जब पानी ओवरफ्लो हो रहा था, तभी संबंधित विभाग और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था।

विधायक ने भी आरोप लगाया कि बांध में मछली पालने वालों ठेकेदारों का कब्जा है। उन्होंने ही बांध के गेट को खोलने से रोका है, जिसकी वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है।

हाथियों ने घर में सो रहे 2 सगे भाइयों को कुचला

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती देर रात एक दंतैल हाथी ने घर में सो रहे दो लोगों को कुचल कर मार डाला। दोनों मृतक सगे भाई बताया जा रहे हैं। तपकरा वन परिक्षेत्र में बीते एक पखवाड़े से जंगली हाथी दहशत फैला रहे हैं। इस दौरान हाथी ने कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। केरसई गांव में बीती रात 2 से 3 बजे के बीच कच्चे मकान में सो रहे 2 सगे भाइयों को एक दंतैल हाथी ने बारी बारी से कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि हाथी ने पहले मकान तोड़ना शुरू किया। इसकी आहट सुनकर जब एक भाई बाहर आने लगा तो दंतैल ने उसे सूंड में लपेटकर पटकना शुरू कर दिया और ये देखकर दूसरा भाई बचाने पहुंचा तो हाथी उस पर भी टूट पड़ा और उसकी भी जान ले ली। हाथी के हमले से कोकड़े 45 वर्ष, पड़वा 43 वर्ष की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय भी घटना पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हाथी के हमले में 2 मौत हुई है। पंचनामा सहित विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। जंगल के अंदर घर बनाकर रहने वालों को वहां से निकलकर सामुदायिक भवन में रखा जा रहा है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

■ जारी हुआ नोटिस

बालोद। बालोद जिले के गुरूर थाने में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बीते 12 जुलाई को गुरुर नगर में अवैध व्यावसायिक परिसर को तोड़े जाने और उसे दौरान उत्पन्न हुए विवाद सहित अन्य मामलों को लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसके बाद राजनैतिक हलचल बढ़ गई है पूर्व विधायक को थाने में उपस्थित होने नोटिस जारी किया गया है और जांच में सहयोग करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को तोड़े जाने के विषय को लेकर पूर्व विधायक और विधायक ने रोकने का प्रयास किया था विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, इस दौरान कुछ महिलाओं ने नगर की महिला पार्षद कुंती सिन्हा को घसीटकर सड़क में ले जाकर पटक दिया था।

कांग्रेस के पूर्व विधायक भैय्या राम सिन्हा पर गुरुर पुलिस ने घर मे घुसकर मारपीट, बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूर्व विधायक भैय्या राम सिन्हा को गुरुर पुलिस ने विवेचना के दौरान सहयोग करने नोटिस जारी किया। भविष्य में कोई अपराध न करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने, मामले में तथ्यों से परिचित किसी को धमकी या प्रलोभन न देने, जांच में सहयोग करने नोटिस के माध्यम से गुरुर पुलिस ने पूर्व विधायक को निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि धारा 35 के उपधारा (3) बीएनएसएस के अंतर्गत थारा 333, 296, 115(2), 351(2), 191(2), 3(5) बी.एन.एस. जो थाना चौकी गुरूर जिला बालोद के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है इसके तहत नोटिस जारी किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दिन की पूरी घटना है, इसी मामले में पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा सहित अन्य 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यानी अब तक कुल 8 लोगों के खिलाफ गुरुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

13 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली रानीता ने किया सरेंडर

कबीरधाम। शनिवार को कवर्धा के ट्रैफिक प्लाजा के मीटिंग हॉल में तीन राज्य की 13 लाख रुपए इनामी महिला नक्सली रानीता ने सरेंडर कर दिया है। इस नक्सली के खिलाफ एमपी के बालाघाट जिले में 19 व सीजी के केसीजी जिले में 3 अपराध दर्ज है। महिला नक्सली गोंदिया-राजनांदगांव-बालाघाट, जीआरबी डिवीज़न अंतर्गत टांडा/मलाजखंड एरिया कमेटी सदस्य के रूप में सक्रीय थी। इस पर छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए, मध्यप्रदेश राज्य में 3 लाख रुपए व महाराष्ट्र राज्य में 5 लाख रुपए इनाम घोषित है।

महिला नक्सली पर कुल 13 लाख का इनाम घोषित है। छत्तीसगढ़ शासन के नक्सल उन्मूलन व नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। कबीरधाम एसपी डॉ.अभिषेक पल्लव ने बताया कि महिला नक्सली रानीता उर्फ हिड़मे कोवासी पति प्रेम पिता सन्नू कोवासी उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी पुलनपाड़, गोल्लापरा थाना चिंतलनार जिला सुकमा ने जून 2016 में किस्टाराम एरिया में बाल संगम में शामिल हुई। इसके बाद जनवरी-फरवरी 2024 तक संगठन में सक्रिय रूप से काम किया। ये एमपी, सीजी व महाराष्ट्र में सक्रिय रहीं है। आत्मसमर्पित महिला नक्सली को पुनर्वास नीति के तहत मौके पर ही कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे के हाथों 25 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान की गई। इसके साथ छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जून 2016 में किस्टाराम एरिया में बाल संगम में शामिल हुई। वर्ष 2017 में संगठन में पूर्ण सदस्य बनी। 6 माह किस्टाराम क्षेत्र में रही। सितंबर 2017 में विस्तार के लिए एमएमसी जाने कोतुल एरिया माड़

आई। माड़ क्षेत्र से 20 लोगों के साथ विस्तार के लिए एमएमसी में आकर टांडा एरिया पहुंची। अक्टूबर2017 से 2020 तक टांडा एरिया कमेटी में रही। वर्ष 2021 से टांडा एरिया कमेटी को समाप्त कर मलाजखंड व दरेकसा में शामिल करने पर मलाजखंड एरिया कमेटी में सदस्य के रूप में जनवरी-फरवरी 2024 तक सक्रिय रही। मलाजखंड एरिया में एसजेडसीएम/डिवीजन सचिव विकास नागपुरे के साथ रही। संगठन में 2022 में संगठन में मलाजखंड एरिया कमेटी कमांडर के साथ शादी हुआ था। एक साल बाद पति-पत्नी अलग हो गए। संगठन में छोटे स्तर के कैडर के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार के कारण संगठन छोड़ दी। जिला पुलिस कबीरधाम ने मीडिया के माध्यम से नक्सल संगठन में कार्यरत सभी लोगों से अपील किया है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो। एक स्वस्थ, सुरक्षित व खुशहाल जीवन जीएं। हमारा उद्देश्य सभी भटके हुए युवाओं को पुनर्वासित कर उन्हें सम्मानित और समृद्ध जीवन प्रदान करना है। हिंसा का मार्ग छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले सभी व्यक्तियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत हर संभव सहायता व सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

बलरामपुर के राजपुर में नर्सों को बदसलूकी पड़ी महंगी, कलेक्टर ने लिया एक्शन

बलरामपुर। बलरामपुर के कलेक्टर ने मरीजों से बदसलूकी करने वाले नर्सों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के राजपुर में एक छात्रावास की अधीक्षिका हॉस्टल के बच्चों का इलाज कराने पहुंची थी। नर्सों पर इलाज के दौरान शिक्षिका से बदतमीजी का आरोप लगा। यह पूरी घटना की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी उन्होंने एक्शन लिया और नर्सों को सस्पेंड कर दिया।

बलरामपुर के राजपुर में राजीव पहड़ा छात्रावास संचालित है। यह पूर्व सांसद नंद कुमार साय के नाम पर चल रहा है। यहां के चार बच्चे इलाज के लिए अपने टीचर के साथ राजीव पड़हा हॉस्टल में गुरुवार को पहुंचे थे। शिक्षिका के मुताबिक इलाज के दौरान उनके साथ नर्सों ने बदसलूकी की। नर्स के पास से पर्ची बनवाने के बाद सभी लोग डॉक्टर के पास गए। वहां से आने के बाद इंजेक्शन लगाने के लिए पर्ची नर्स को दे दिया। इनमें चार में से दो पर्ची नर्स ने कहीं रख दिया इन बच्चों और मैडम पर नर्स पर्ची गुमाने का आरोप लगाकर चिल्लाने लगी

हद तो तब हो गई जब नर्सों ने शिक्षिका और बच्चों को अस्पताल में आने से मना कर दिया। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया। जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी वीडियो और शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने शनिवार को नर्सों के निलंबन की कार्रवाई की है। नर्स आंचल सिंह और रजनी तिर्की को निलंबित किया गया है।

इस पूरी घटना पर राजपुर विकासखंड के चिकित्सा अधिकारी रामप्रसाद ने मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद दोनों नर्सों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया। जवाब के बाद दोनों नर्सों को कलेक्टर ने सस्पेंड किया है। कलेक्टर के आदेश में यह जिक्र है कि नर्सों ने मरीजों के साथ बदतमीजी की है। जो उनके दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत है। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जांगला पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी, सैकड़ो यात्री फंसे

बीजापुर। बीजापुर में इन दिनों सावन की

झड़ी से बीजापुर जिला तरबतर हो गया है। अनवरत हो रही बारिश से बीजापुर टापू में तब्दील हो गया है। शनिवार को बारिश की वजह से एक बार फिर जांगला के पास नेशनल हाईवे 63 के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने से बीजापुर से जगदलपुर मार्ग सुबह से बंद हो गया है। इस मार्ग पर सुबह से यात्री आवागमन बंद है। मार्ग बंद होने से इस मार्ग पर सफर करने वाले राहगीर परेशान नजर आ रहे है। उन्हें अब बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रहे है। जांगला थाना प्रभारी दीपक ठाकुर ने बताया की सुबह तक़रीबन 7.30 बजे जांगला के पास बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है जिस वजह से आवागमन बाधित हो गया है।

पंप सुधारने के लिए कुएं में उतरे तीन लोगों की मौत

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं में कुएं के अंदर पंप सुधारने के लिए उतरे तीन लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर नवागढ़ पुलिस व नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे ने बताया कि खेत के कुंए में पहले से पंप लगा हुआ था। इसे सुधारने के लिए सबसे पहले दो लोग उतरे थे। इसके बाद वो वापस नहीं आए। फिर तीसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, वो भी वापस नहीं आया। मौके पर रेस्क्यू के लिए दुर्ग से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। उनके आने के बाद कुएं के अंदर मौजूद लोगों को निकाला जाएगा। इस कुएं में आत्माराम साहू पिता परदेशी साहू उम्र 55 वर्ष, राकेश साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 25 वर्ष, रामकुमार ध्रुव पिता रामलाल उम्र 45 वर्ष उतरे हैं, जो अब तक नहीं निकल सके हैं। कुएं के आसपास किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया रहा है।

शराब की दुकान में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग। दुर्ग जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में शासकीय शराब दुकान में अज्ञात चोरों ने गल्ले में रखे लाखों रुपये चोरी कर फरार हो गए।चोर की सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नयापारा देशी शराब दुकान में 25 और 26 जुलाई की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों के द्वारा शराब दुकान के गल्ले में रखे करीब 11 लाख रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। शराब दुकान को मुंबई इंट्रारग्रेटेड सीक्रेट इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आरोपियों ने आसानी से दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसकर दुकान के गल्ले से लगभग 11 लाख चोरी कर फरार हो गए। इस शराब दुकान में रात के समय एक सुरक्षा कर्मचारी की भी ड्यूटी लगाई गई थी जो घटना के समय सो रहा था। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि शराब दुकान में चोरी की घटना घटित हुई है घटना करने वाले आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज में आया है शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है।

10 साल बाद मिली गुमशुदा नाबालिग

कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने 10 साल पहले गुमशुदा हुई एक नाबालिग लड़की को यूपी के उन्नाव जिले से खोज निकाला है। लेकिन, जब पुलिस ने लड़की को बरामद किया तो आज 2024 में वह बालिग हो चुकी है। इतना ही नहीं लड़की की शादी हो चुकी है। पूरा मामला कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र का है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि गणेश केवट निवासी ग्राम अचानकपुर ने चार जनवरी 2015 को अपनी नाबालिक लड़की की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला 10 साल पुराना था। इसकी फाइल थाना में धूल खा रही थी। एसपी के निर्देश पर पुराने पेंडिंग मामले का निपटारा किया जा रहा है। इस मामले की जांच शुरू हुई। केश डायरी अवलोकन करने पर आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड नंबर को सीएससी सेंटर में सर्च कराया गया। तब आधार नंबर से ग्राम मवई घनश्याम बांगरमऊ जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के पते पर किसी दूसरी महिला के नाम पर राशन कार्ड बना होना पाया गया। उसी आधार नंबर में गुमशुदा नाबालिक का नाम दर्ज होना पाया गया।

दो बाइकों में आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हो रहे सड़क हादसों में बेगुनाहों की जान जा रही है। बीती रात एक बार फिर दो बाईकों की आमने-सामने भिड़ंत की घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य को गंभीर अवस्था में रायगढ़ मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में बीती देर रात दो बाईक की एक बार फिर आमने-सामने भिड़त हो गई। जिसमें एक युवक की सिर के अलावा शरीर के अन्य हिस्सा में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई तो वहीं एक अन्य युवक को गंभीर हालत में रायगढ़ मेडिकल कालेज रिफर किया गया है जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि जीत राम तिर्की बीती रात धरमजयगढ़ से कापू की तरफ जा रहा था इसी दौरान सामने की तरफ से आ रहे कुपा गांव निवासी एक अन्य युवक धरमजयगढ़ की ओर आ रहा था।

4 आदिवासी कमार जनजाति गांव में पहुंची बिजली

गरियाबंद। बिजली की रौशनी मिलने की खुशी क्या होती है यह आदिवासी कमार बाहुल्य ग्राम भीरालाट के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ही महसुस किया जा सकता है। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दुर नेशनल हाईवे मैनपुर गरियाबंद मुख्य मार्ग के किनारे बसे ग्राम पंचायत जोबा के आश्रित ग्राम भीरालाट बिजली की रौशनी पहुचने में 75 वर्ष का समय लग गया और अब जब गांव में बिजली की रौशनी पहुंची तो ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए खुशी जाहिर किया है और साथ ही मुख्यमंत्री साय को अपने गांव आने का निमंत्रण भी दिया है।

गरियाबंद जिले के दर्जनों गांव में बिजली लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना जो विशेष पिछड़ी

जनजातियों के लिए संचालित की जा रही है। पीएम जनमन योजना के तहत लगातार मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के छिंदौला, लूठापारा में तीन माह पूर्व ही बिजली की रौशनी पहुंचाई जा चुकी थी। तो वहीं नेशनल हाईवे मैनपुर गरियाबंद मार्ग में बसे कमार बाहुल्य पारा भीरालाट जिसमें लगभग 15 से 18 कमार जनजाति परिवार के लोग निवास करते हैं, यहां के ग्रामीण कई बार बिजली की मांग करते-करते थक चुके थे। अब साय सरकार ने इस गांव को बिजली से रौशन कर दिया है।

गरियाबंद जिला कलेक्टर दीपक अग्रवाल के सक्रियता और लगातार दिशा निर्देश के बाद बिजली विभाग गरियाबंद के कार्यपालन अभियंता अतुल तिवारी के विशेष प्रयास से पीएम जनमन योजना के तहत ग्राम भीरालाट में एक महीने पहले सर्वे कर गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया और इस गांव के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार ग्रामीणों के 15 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है।

एक हफ्ते पहले यहां बिजली कनेक्शन लगाकर इसका ट्रायल किया गया। इसके बाद इसे विधिवत शुरू किया गया। बारिश के मौसम के बीच गांव में बिजली की रौशनी पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने इसके लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। ग्राम पंचायत जोबा के आश्रित ग्राम पारा भीरालाट को बिजली की रौशनी मिलने से लालटेन से छुटकारा मिल गया है।

आठ लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। धमतरी जिले के साइबर और कुरूद पुलिस ने कुछ दिन पहले एक घर मे हुई चोरी का खुलासा किया है।पुलिस इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किये गए सोने चांदी के आभूषण बरामद किया है। बताया गया कि 6 जुलाई को कुरूद के अमृत विहार कालोनी के राजेश कुमार साहू ने अपने घर में ताला लगाकर अपने परिवार के साथ अपने ग्रह ग्राम गया था। तभी सुने मकान में कुछ आज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषण सहित नगदी रकम कीमत लगभग 8 लाख रुपए को चोरी कर लिया गया था। वहीं जब पीड़ित घर पहुंचा, तो उसे घर मे चोरी होने का पता चला। जिस पर पीड़ित द्वारा 7 जुलाई को कुरूद थाना आकार रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

वही सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस और धमतरी साइबर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की पता तलाश में जुड़ गई थी।इस दौरान मुखबिर के सूचना और सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर संदेहियों सागर निर्मलकर, सूरज साहू, आशीष देवांगन सभी निवासी दुर्गानगर अम्लेश्वर जिला दुर्ग को पकड़कर पूछताछ किया गया। जिस पर आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया और इसके साथ ही बताया कि 11 जुलाई को कचना बस स्टेण्ड के साहू होटल के शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर घुसकर चोरी का प्रयास करने बताया।

वहीं गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से साढ़े 6 लाख रुपए करीब के सोने चांदी के आभूषण, दो मोटरसाइकिल सहित इलेक्ट्रानिक कटर मशीन को जब्त किया गया है।पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज गया है। बरहाल पुलिस का कहना है कि यह तीनों आदतन अपराधी है जो की धमतरी जिले सहित आसपास के जिलों में भी रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते आए हैं।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की समाप्ति पर सभी को धन्यवाद किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन की समाप्ति पर सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से सदन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। डॉ. सिंह ने विशेष रूप से उन सदस्यों की सराहना की जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी और विधायकों के बीच स्वस्थ चर्चा और विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी कहा कि सदन के सभी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस सत्र के दौरान पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों का भी उल्लेख किया और कहा कि ये विधेयक राज्य के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण साबित होंगे।अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने सभी को शुभकामनाएँ देते हुए सदन की समाप्ति की घोषणा की और कहा कि वह भविष्य में भी सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

महापौर ढेबर व अन्य पर एफआईआर

रायपुर। विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को रोकने के बीच कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झूमाझटकी हो गई थी। महापौर एजाज ढेबर, आशीष द्विवेदी समेत कुछ अन्य के खिलाफ वीडियो फूटेज के आधार पर पुलिस कर्मियों ने ही पुलिस से गाली-गलौच और धक्कामुक्की किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप है बिना अनुमति विधानसभा घेराव के लिए रास्ता बाधित किया गया। शासकीय सेवकों के साथ ड्यूटी के बीच इस प्रकार का कृत्य अपराध के दायरे में आता है। इसी आधार पर एफआईआर करायी गई है। उधर महापौर ढेबर ने कहा है कि राजनीतिक द्वेषवश यह एफआईआर करायी गई है,जनहित के मुद्दों पर धरना-प्रदर्शन यदि राजनीतिक दल व उनके प्रतिनिधि नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक झमाझम बारिश के आसार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इससे नदी-नाले उफान पर हैं। कई पुल भी ढह गए हैं। इसके साथ ही कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। आज शनिवार को प्रदेशभर में बारिश के आसार हैं। मानसून सक्रीय होने की वजह से अगले दो दिनों तक प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के तटीय इलाकों और गंगीय पश्चिम बंगाल पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकते हुए औसत समुद्र तल से 7.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले दो दिनों के दौरान इसके गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ सक्रिय है। अपनी सामान्य स्थिति के करीब है। अगले चार-पांच दिनों के दौरान इसके सामान्य स्थिति के करीब बने रहने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार, मानसून सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के अधिकांश जगहों पर हल्की मध्यम और एक-दो जगह पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले दो दिनों में प्रदेशभर में भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। यहां शाम तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

रेलवे स्टेशन पर बिस्किट चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, चार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बिस्किट

चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में जीआपी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं वहीं 1 सहायक उप निरीक्षक 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर एक युवक दुकान से बिस्किट चोरी कर रहा था, तभी दुकानदार की नजर उस पर पड़ गई। दुकानदार ने युवक को पकड़कर उसके हाथ-पैर बांध दिए और बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उसके पैरों को कपड़े से बांधकर प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए चार आरोपियो को गिफ्तार किया और रायपुर रेल मंडल के कमांडेंट ने 1 सहायक उप निरीक्षक और 2 महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।

विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला, और किसान : मांडविया

नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करेगी सरकार

रायपुर। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुखभाई मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट में चार पिलर तैयार किया है। विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला, और किसान है, केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्हें कृषि, रोजगार और कौशल, बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलेपन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेश टोटल में सोचते हैं। इसलिए अमृतकाल का विजन दिया है। आजादी के 100 साल बाद देश विकसित राष्ट्र हो, इसका रास्ता बताया है। गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा के विकास

पर फोकस किया। इन चार पिलर के विकास के लिय 9 प्राथमिकता तय किया है। किसान की लागत से डेढ़ गुना दाम पर उपज खरीदते है। 1.52 लाख करोड़ किसानों के लिए दिए है। ऑर्गेनिक खेती के नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे प्रावधान किए है। लैंड रिकॉर्ड सुधार, टाइटल सुधार पर फोकस किया गया। 1.48 लाख करोड़ का खर्च रोजगार लिंक इंसेंटिव पर होगा। युवा और रोजगार केंद्रित बजट है ये स्किल विकास के लिए विकेंद्रित एमएसएमई विकास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सालाना 1 करोड़ युवा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश के टॉप 400 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगा। पांच साल में 4 करोड़ युवा को रोजगार लायक बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल में ई प्लेटफॉर्म तैयार होगा। छोटे छोटे उद्यमी, कलाकार के उत्पाद को यहां जोड़ेंगे। 100 सिटी में मॉडल फूड स्ट्रीट तैयार कराएंगे। 1 करोड़ शहरी निवास के 10 लाख करोड़ देगी। 30 से 32 किमी प्रतिदिन एनएच रोड बन रहा। अमेरिका भी प्रतिदिन 30 किमी एनएच नही बना सका।

इस मौके पर भाजपाध्यक्ष किरण सिंह देव,सांसद बृजमोहन अग्रवाल,छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेता, ओ पी चौधरी, टंकराम वर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

हसदेव अरण्य में पर्यावरण क्षरण पर लोकसभा में हुई चर्चा

■ वन विभाग ने 50 लाख से अधिक वृक्षारोपण की दी जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पर्यावरण क्षरण के संबंध में लोकसभा प्रश्न के उत्तर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक (वन्यजीव प्रभाग) को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें साल 2023 तक, परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान में खनन के लिए प्रतिपूरक उपायों के रूप में, वनीकरण, खदान सुधार और स्थानांतरण प्रयासों के लिए कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं। इन नए लगाए गए पेड़ों में से लगभग 40,97,395 जीवित पेड़ हैं। वहीं खनन के लिए 94,460 पेड़ों का विदोहन किया गया है।

आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद श्री संदीप कुमार पाठक द्वारा उठाए गए प्रश्न में हसदेव अरण्य में पर्यावरणीय प्रभाव के कई पहलुओं पर जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों पर अलग से कोई अध्ययन नहीं किया है। हालांकि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के निर्देशों के बाद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के साथ मिलकर जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन किया और सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की

सिफारिश नहीं की गई है।

वहीं इस क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए आने वाले कई वर्षों में अनुमानित 2,73,757 पेड़ों का विदोहन किये जाने की उम्मीद है। इस जानकारी का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चिंताओं तथा हसदेव अरण्य में शमन और पुनरुद्धार की दिशा में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालना है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरआरवीयूएनएल) अपने बिजली उत्पादन संयंत्रों की कोयले की मांगों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तीन उपयुक्त कोयला खदानों का मालिक है। आरआरवीयूएनएल पहले से ही परसा ईस्ट कांता बासन ब्लॉक का संचालन कर रहा है और औद्योगीकरण और नौकरियों से वंचित इस जिले में करीब 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। राजस्थान सरकार का निगम छत्तीसगढ़ सरकार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर, रॉयल्टी और अन्य शुल्क भी देता है। आरआरवीयूएनएल द्वारा अपने दो अन्य परसा और केते एक्सटेंशन ब्लॉकों का संचालन शुरू करने के बाद यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है।

हर वार्ड में लगेंगे शिविर, लोगों के समस्याओं का मौके पर होगा समाधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।

राज्य शासन द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निकाय का मुख्य

दायित्व है। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर, नागरिकों की उमड़ी भीड़

गौरव और निकिता का बना आय प्रमाण पत्र, किशोर को राशन कार्ड से मिलेगा निःशुल्क चावल

रायपुर। नगरीय निकायों में आज से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का वार्डों में लगने शुरू हो गए है। शिविर में नागरिक पहुंचकर अपनी समस्याओं को दर्ज करा रहे है और उसका समाधान भी त्वरित दिलाया जा रहा है। नागरिकों में शिविर को लेकर उत्साह है।

टिकरापारा के शिविर में इंजीनियरिंग छात्र गौरव यादव और 12 वीं की छात्रा निकिता यादव ने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पटवारी को आवेदन किया। तत्काल पटवारी ने आय प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें सौंप दिया। त्वरित कार्य होने से छात्रों और परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त की। इसी तरह टिकरापारा के श्री किशोर सिन्हा ने राशन कार्ड बनने के बाद चावल नहीं मिलने की समस्या दर्ज कराई। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही उनकी समस्या का हल निकाला और उनके दस्तावेजों को अपडेट किया गया। श्री किशोर के राशन कार्ड की त्रुटि को सही कर दिया गया। उन्हें जल्द ही राशन दुकान से निःशुल्क चावल मिलेगा। निराकरण होने से वे और उनका परिवार काफी खुश है। सिविल लाइंस के अंबेडकर भवन में भी शिविर लगाए गए है। इस शिविर में लोग अपनी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर पहुंचे।

अपनी समस्याओं को दर्ज कराया है। समस्या निवारण शिविर में हेल्थ कैंप का लाभ दिया गया। इसमें रेविका मसीह, सिया राम घृतलहरे समेत अनेकों को हेल्थ चेकअप का लाभ मिला। इसी तरह आधार कार्ड, पेंशन संबंधी समस्याओं को दर्ज कराई गई।

जोन क्रमांक 2 में जनसमस्या निवारण शिविर में नागरिकों का उत्साह दिखाई दिया। शिविर में पहुंचकर लोगों ने अपनी समस्याओं को दर्ज कराई। मौदहापारा निवासी श्रीमती शहनाज बेगम ने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराया हनवीनीकरण के बाद अब उन्हें निःशुल्क चावल भी मिलेगा। इसी तरह अन्य समस्याओं को लेकर भी वहां लोग पहुंचे। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

बृजमोहन पहुंचे जनसमस्या निवारण शिविर में

जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर के पहले दिन जोन-6 के शिविर में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। सांसद श्री अग्रवाल ने शिविर के अलग-अलग विभागों के स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली और पीएम पीएम सौर घर योजना का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को दिलाने को कहा। सांसद श्री अग्रवाल ने अन्य विभागों के स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली।

कमल विहार में आशियाना दिलाने के नाम पर 32 परिवारों से लाखों की ठगी

रायपुर। राजधानी के कमल विहार में मकान दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जहां बंटी-बबली और उसके सहयोगी ने मिलकर लालपुर में एक ऑफिस खोलकर 32 गरीब परिवारों को सपनों का घर दिलवाने का झांसा दिया देकर लाखों की ठगी की। जिसके बाद आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो गए। पीड़ितों शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी अभय यादव, उसकी गर्लफ्रेंड और सहयोगी निहाल यादव ने लालपुर में एक ऑफिस खोला। जिसके बाद आरोपियों ने लोगों को सपनों का घर दिलवाने का झांसा दिया। आरोपियों के झांसे में करीब 32 गरीब परिवार आए और साल 2022 से 2024 तक पीड़ितों से लगभग 90 लाख रुपये की ठगी कर आरोपी ऑफिस बंद कर रफूचक्कर हो गए। लोगों ने खुद को ठगी महसूस होने के बाद टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले ने बताया कि कौशल्या विहार में मकान दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 32 पीड़ितों की शिकायत पर अपराध दर्ज किया है। आने वाले समय में पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

टिकरापारा थाना प्रभारी मनोज साहू ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2022 से 2024 तक में आरोपियो ने कुल 32 लोगों से 90 लाख रुपये ठगे हैं। आरोपियों की पतासाजी में टीम तैयार की गई है। आरोपियों का लोकल नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्हीं के माध्यम से आरोपियों तक पुलिस टीम पहुंचेगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 31/नि.शा./का.अ./ लो.स्वा. या / खण्ड, रायपुर, दिनांक 09.07.2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है-

स क्रं.	कार्य का नाम	ठेके की राशि (रु.लाख में)
1.	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना के अंतर्गत जलशुद्धिकरण संयंत्र के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं अन्य सिविल कार्य (समस्त सामग्री सहित)।	9.65

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29.07.2024 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
रायपुर छत्तीसगढ़

जी- 242501357/2

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर, (छग)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal :- https://eproc.cgstate.gov.in

निविदा निरस्तीकरण सूचना

आदेश क्रमांक 2112 / व.ले.लि./2024-25/गरियाबंद दिनांक 24/07/2024

निविदा क्रमांक 23/व.ले.लि./2023-24 दिनांक 28.02.2024 सिस्टम क्रमांक 153379 तृतीय आमंत्रण इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित गरियाबंद जिले के विकासखण्ड फिंगेश्वर की पैरी परियोजना अंतर्गत पितईबंद माईनर नहर के कोमा सब माईनर क्रमांक 01 के आर.डी. 0 मी. से 815 मी., कोमा सब माईनर क्रमांक 02 के आर.डी. 0 मी से 910 मी., राजिम सब माईनर के आर.डी. 0 मी. से 1200 मी., सेम्हरतरा सब माईनर के आर.डी. 0 मी. से 1915 मी.. पितईबंद माईनर के आर.डी. 3210 मी. से 7650 मी., पितईबंद सब माईनर क्रमांक 01 कि आर.डी. 0 भी. से 600 मी. एवं सब माईनर क्रमांक 02 के आर.डी. 0 से 750 मी. तक जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य तथा 02 नग व्ही.आर.बी. का निर्माण कार्य तृतीय आमंत्रण की ऑनलाईन निविदा में प्रतिभागी निविदाकार की संख्या निरंक होने के फलस्वरूप उक्त निविदा को निरस्त किया जाता हैं।

विज्ञापन क्रमांक 08209 / दिनांक 28.02.2024

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन विभाग गरियाबंद
कृते, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
रायपुर (छग)

जी- 242501370/6

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना
(प्रथम आमंत्रण)

दिनांक 24.07.2023

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा डी श्रेणी एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 12.08.2024 है।

एन.आई.टी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
NIT No. 297 Tender No. 156536	धमतरी अनुविभाग के अन्तर्गत आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं मरम्मत का कार्य।	रू. 95.00 लाख
NIT No. 298 Tender No. 156537	धमतरी अनुविभाग के अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं मरम्मत का कार्य।	रू. 130.00 लाख
NIT No. 299 Tender No. 156538	गरियाबंद अनुविभाग क्रमांक 01 के अन्तर्गत उपखण्ड क्रमांक 01 के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत का कार्य।	रू. 40.00 लाख
NIT No. 300 Tender No. 156539	गरियाबंद अनुविभाग क्रमांक 01 के अन्तर्गत उपखण्ड क्रमांक 01 के आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत का कार्य।	रू. 25.00 लाख
NIT No. 301 Tender No. 156540	गरियाबंद अनुविभाग क्रमांक 01 के अन्तर्गत उपखण्ड क्रमांक 02 के गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत का कार्य।	रू. 40.00 लाख
NIT No. 302 Tender No. 156541	गरियाबंद अनुविभाग क्रमांक 01 के अन्तर्गत उपखण्ड क्रमांक 02 के आवासीय भवनों में रंगाई पोताई एवं साधारण मरम्मत का कार्य।	रू. 25.00 लाख
NIT No. 303 Tender No. 156542	नगरी अनुविभाग के अन्तर्गत गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य।	रू. 50.00 लाख
NIT No. 304 Tender No. 156543	नगरी अनुविभाग के अन्तर्गत आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य।	रू. 50.00 लाख
NIT No. 305 Tender No. 156544	जिला महासमुन्द के उपसंभाग सरायपाली अंतर्गत शासकीय गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	रू. 50.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेवपोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र बिडकेपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

विश्वसनीय छत्तीसगढ़
जी- 242501341/9

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि. रायपुर मण्डल क्र. 2 (छग)

आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

नयी सरकार में निरंतरता को प्रमुखता

प्रभु चावला

बीते लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने निरंतरता के लिए जनादेश दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार का गठन किया। इस परिणाम में थोड़ा बदलाव कर गठबंधन सरकार के लिए जनादेश था। पिछले कुछ हफ्तों में मोदी सरकार के क्रियाकलापों को देखकर लगता है कि निरंतरता बदलाव पर हावी हो गयी है। मंत्रिपरिषद का रंग जरूर बदला है, तौर-तरीकों, संविधान, भारत की रणनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक राह में कोई खास अंतर नहीं आया है। भले ही कांग्रेस की राजनीति तीन बार परास्त हुई हो, पर उसके आर्थिक और कूटनीतिक तौर-तरीकों को नयी सरकार में भी गौरवपूर्ण जगह मिली है। नेहरूवादी व्यवस्था से संबंधित अर्थशास्त्रियों को इस सरकार में पहले की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। मसलन, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें सभी पांच पूर्णकालिक सदस्यों- उपाध्यक्ष सुमन बेरी, विजय कुमार सारस्वत, अरविंद विरमानी, रमेश चंद और डॉ वीके पॉल- को फिर से शामिल किया गया है। भाजपा नेताओं के लिए 75 साल की आयु सीमा है, पर यह नियम नीति आयोग में लागू नहीं होता। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और शेष सदस्य राज्य मंत्री स्तर के होते हैं। गठबंधन की मजबूरी के कारण कुछ नये कैबिनेट मंत्रियों को सदस्य और आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, पर मुख्य टीम पुरानी ही है। बेरी, विरमानी और सारस्वत की उम्र 75 साल से अधिक है। रमेश चंद और पॉल के अलावा बाकी यूपीए सरकार से भी संबद्ध थे तथा सीधे या परोक्ष रूप से आंतरिक संगठनों और रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े थे। विश्व बैंक से अपना करियर शुरू करने वाले बेरी कांग्रेस व्यवस्था द्वारा बनाये गये अभिजन बहुराष्ट्रीय मेरिटोक्रेसी तंत्र के खांचे में पूरी तरह सही बैठते हैं। वे रिजर्व बैंक के सलाहकार तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वे ऊर्जा कंपनी शेल से संबद्ध थे तथा ब्रसेल्स स्थित संस्था ब्रूएगल के फेलो रहे हैं, जिससे कई बड़ी तकनीकी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। विरमानी, जिनकी विचारधारा भी उनका अपना करियर है, भी कांग्रेस सरकारों के साथ काम कर चुके हैं तथा उनका जुड़ाव अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी रहा है। यूपीए शासन में वे एक बार मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। प्रमुख वैज्ञानिक माने जाने वाले सारस्वत भी यूपीए सरकार में सचिव थे तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से संबद्ध थे। वे तब विवादों से घिरे रहते थे और एक बार सरकार ने उनकी वित्तीय शक्तियों को सीमित भी कर दिया था। फिर भी मनमोहन सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से नवाजा था। मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके बीवीआर सुब्रमण्यम को आयोग का सीइओ बनाये रखा गया है। साल 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद उन्हें नीति आयोग का सदस्य बना दिया गया था। डॉ पॉल और चंद का भाग्य यूपीए के दौर में ऐसा नहीं था। लगभग 70 वर्ष के हो चुके डॉ पॉल एम्स में लगभग एक दशक तक शिशु रोग विभाग के प्रमुख रहे, पर उन्हें निदेशक नहीं बनाया गया। भाजपा सरकार के आने के बाद उन्हें अगस्त 2017 में नीति आयोग का सदस्य बनाया गया। कृषि अर्थशास्त्री चंद आयोग के सबसे कम आयु के सदस्य हैं। नीति आयोग की प्रशासकीय परिषद के सदस्य के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बेहद अहम साबित होंगे। बीते एक दशक में परिषद की एक दर्जन से भी कम बैठकें हुई हैं। मोदी की तरह नायडू भी विचारवान व्यक्ति हैं और विशेषज्ञों के सहयोग से वे विकास का वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकते हैं, जिससे अधिक निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्यों में वास्तविक विकास तेज होगा। वे अधिकारियों और विदेशों में प्रशिक्षित पेशेवरों को नैरेटिव नहीं गढ़ने देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपनी बैठक के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस-खालिस्तान में गर्भनाल का रिश्ता!

राकेश सैन

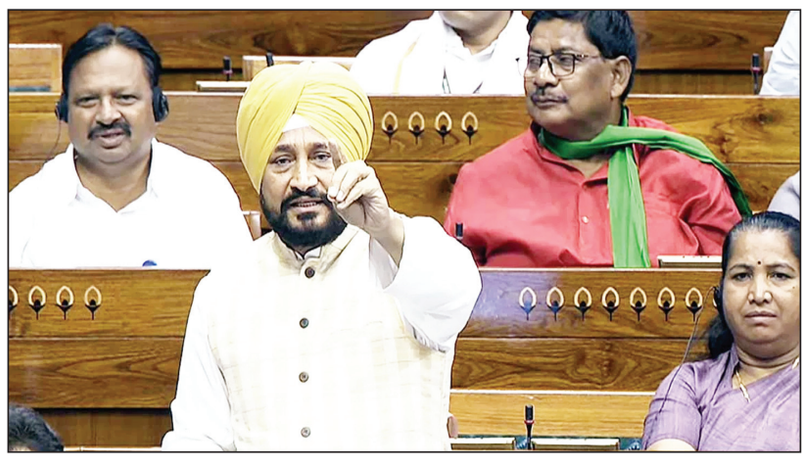

माँ और सन्तान के बीच गर्भनाल का रिश्ता ही ऐसा होता है, कि प्रसव के बाद शरीर अलग होने के बावजूद भी आत्मीयता बनी रहती है। सन्तान को पीड़ा हो तो माँ बिलख उठती है। ऐसा ही गत 25 जुलाई को संसद भवन में देखने को मिला जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालन्धर से कांग्रेस के सांसद चरनजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल के पक्ष में आह भरी। चन्नी के शब्दों में 20 लाख लोगों के खडूर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि अमृतपाल को जेल में रखा जा रहा है, यह भी एमरजेंसी है। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में डिब्रूगढ़ जेल में नजरबन्द खालिस्तान प्रचारक व अजनाला कोतवाली हिंसा का मुख्य आरोपी अमृतपाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है और कांग्रेस सांसद चन्नी लोकसभा में उसके ही पक्ष में बोल रहे थे। रोचक बात तो ये है कि अमृतपाल को जेल में भेजने वाली पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसद भी सुन्न अवस्था में चन्नी के साथ वाली सीटों पर ही बैठे थे।

वैसे चन्नी के बौद्धिक व प्रशासनिक योग्यता के स्तर का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी, 2018 में कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की सरकार के तकनीकी शिक्षा मन्त्री रहते हुए उन्होंने प्राध्यापकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि क्रिकेट की तरह टॉस करके की थी। उस समय देश-दुनिया में इस घटना को बड़े हास्यस्पद अन्दाज में कहा और सुना गया था। बाद में मुख्यमन्त्री बनने के बाद चन्नी प्रधानमन्त्री की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाए और बठिण्डा से फिरोजपुर जाते हुए कथित किसान आन्दोलनकारियों ने प्रधानमन्त्री के काफिले को घेर लिया था। इस पर चन्नी ने सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर डालने का प्रयास किया। केवल इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों के समय जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को चन्नी ने भाजपा की रणनीति बताया था। अब चन्नी द्वारा किसी खालिस्तानी का समर्थन करना चाहे किसी को चौंकाता हो परन्तु 1980 के दशक की राजनीतिक कलाबाजियां देख चुकी पीढ़ी अच्छी तरह जानती है कि चन्नी का अमृतपाल के प्रति दुःख अनायास नहीं बल्कि यह कांग्रेस और खालिस्तान के बीच गर्भनाल के रिश्ते की टीस है।

देश के समक्ष अब यह रहस्य नहीं रहा कि अलगाववादी सोच के व्यक्ति जरनैल सिंह भिण्डरांवाले को पंजाब की अकाली राजनीति को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा और उस पर खालिस्तानी लेबल चस्पा किया। रिसर्च एण्ड एनालाइसेज विंग (रॉ) के सेवानिवृत अधिकारी जी.बी.एस. सिद्धू अपनी पुस्तक 'खालिस्तान षड्यन्त्र की इनसाइड स्टोरी' में दावा करते हैं कि जब भी भिण्डरांवाले से कोई संवाददाता खालिस्तान की मांग के बारे पूछते तो उसका यही जवाब होता था कि- हम खालिस्तान की मांग नहीं करते पर सरकार इसका प्रस्ताव करती है तो हम इन्कार भी नहीं करेंगे।'

चूंकि पंजाब के नर्म दलीय अकाली नेताओं को कमजोर करने के लिए गर्मदलीय लोगों के साथ खालिस्तान का लेबल चस्पा करना जरूरी था, तो 13 अप्रैल, 1978 में हुए निरंकारी-सिख टकराव की घटना के बाद ऐसी शक्ति का खड़ा करना जरूरी हो गया जो खुल कर खालिस्तान की बात करे। चूंकि भिण्डरांवाला न तो खालिस्तान की मांग करने वाला था और न ही विरोध, तो उसके साथ इस बिखराव की मांग को आसानी से जोड़ा जा सकता था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने यह काम बड़ी बाखूबी किया।

उस समय भारत में काम कर रहे बीबीसी लन्दन के पत्रकार मार्क टुल्ली व सतीश जैकब की पुस्तक 'अमृतसर- मिसेज गान्धी लास्ट बैटल' के पृष्ठ 60 पर दावा करते हैं कि 'इस काम के लिए पंजाब में दल खालसा के नाम से कट्टरवादी संगठन का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक चण्डीगढ़ के अरोमा होटल में हुई जिसका 600 रुपये का भुगतान ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया।'

पत्रकार कुलदीप नैयर की पुस्तक 'बियाण्ड द लाइन्स -एन ऑटोबायोग्राफी' के अनुसार, 'इस संगठन के उद्घाटन समारोह में सिख पन्थ की अवधारणा और उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को जीवित रखने का संकल्प लिया गया। संगठन का राजनीतिक उद्देश्य खालसा का बोलबाला बताया गया।'

एक अन्य पत्रकार जीएस चावला अपनी पुस्तक 'ब्लडशेड इन पंजाब- अनटोल्ड सागा ऑफ डिसीट एण्ड सैबोटेज' में लिखते हैं कि- 'दल खालसा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पहले चण्डीगढ़ में एक पूर्व कांग्रेसी सांसद के यहां स्टेनोग्राफर की नौकरी की थी। 6 अगस्त, 1978 को चण्डीगढ़ के सेक्टर 35 में स्थित गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यह घोषणा की गई कि दल खालसा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र सिख साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित करना है। अगले दिन पंजाब के कई समाचारपत्रों में यह खबर छपी, प्रेस कान्फ्रेंस का खर्चा भी पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने उठाया।'

देश के सुविख्यात विचारक कुप्पहल्ली सीतारामैया सुदर्शन अपनी पुस्तक 'यों भटका पंजाब' में लिखते हैं कि-'कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने भी पंजाब समस्या को उग्र बनाने में बहुत मदद दी है। केवल दलीय दृष्टिकोण से ही समस्याओं को देखने का उसका स्वभाव रहा है, इसलिए सत्ताहीन अवस्था में अकाली दल को शह देने के लिए उसने भिण्डरावाले को उभारा। कांग्रेस की आपसी धड़ेबन्दी ने भिण्डरावाले की उग्रता के विरुद्ध समय रहते कड़े कदम उठाने नहीं दिये और जब भिण्डरावाले ने भस्मासुर का रूप लेकर अपने वरदाता को ही भस्म करने के लिए हाथ बढ़ाया तब कांग्रेसी शासन को ऐसी कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ा जिसने समाज में अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया तथा उग्रपन्थियों को खुलकर खेलने का मौका दे दिया।' देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर काडर तक किस तरह दिशाभ्रम के शिकार हैं इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि पार्टी एक तरफ तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी, श्री राजीव गान्धी व स. बेअन्त सिंह को आतंकियों के हाथों मिली शहादत की विरासत अपना बताती है तो दूसरी ओर अमृतपाल जैसों के दुःख में पतली होती रही है। और अधिक विस्मयकारी बात तो यह है कि चन्नी को वहां बैठे किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने ऐसा करने से रोका तक नहीं और न ही बाद में खेद जताया गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद व आतंकवाद की आग दबी जरूर है परन्तु पूरी तरह बुझी नहीं। इसका साक्षात् उदाहरण है कि कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में खालिस्तानियों की खुराफात दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इन देशों में हिन्दू समाज, मन्दिरों व संस्थानों पर हमले, सोशल मीडिया पर विषैला प्रचार निरन्तर जारी है। ऐसे में खालिस्तानी आतंकवाद को देश की संसद में समर्थन मिलता है तो यह गलती भिण्डरांवाले के पुनर्जीवन सरीखी होगी।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-4)

गतांक से आगे...

हम पुराणों की आलोचना करने का दम भरने वाले महाशयों से पूछना चाहते हैं कि आपने कभी वेद-क्रम की विरुद्धता पर भी कुछ विचार किया है।

वस्तुत: क्रम-विन्यास कवि की भावना पर निर्भर होता है। वह जिन भावों से प्रेरित होकर जिस वस्तु स्थिति को अपने क्रम से अभिव्यक्त करना चाहेगा उसी रूप में अपनी कृति को निबद्ध करेगा; उदाहरणार्थ- (1) सर्ववेद-भाष्यकार सायणाचार्य्य ने चारों वेदों पर भाष्य रचते हुये यजुर्वेद को ही प्रथम स्थान दिया है।

(2) श्रीमद्भगवद्गीता में- वेदानां सामवेदोऽस्मि कहकर सामवेद को ही अपनी विभूति प्रकट किया है। जिससे गीता की दृष्टि में सामवेद की मुख्यता एवं प्रथमता स्पष्ट है।

(3) यास्कादि आचार्यों की सम्मति में- और वर्तमानकालीन पौरस्त्य ववं पाश्चात्य समालोचकों के विचार में ऋग्वेद ही सर्वश्रेष्ठ मुख्य - प्रथम मानने योग्य है।

इन विविध विचार-धाराओं का सामंजस्य करने के लिये तत्तद् वक्ताओं की भावनाओं का पता लगाना आवश्यक है। हमारे विचार में यजुर्वेद की प्रथमता प्रकट करने वाले सायणादि की भावना में वेदों की प्रवृत्ति केवल यज्ञ के लिये है, और यज्ञों की इतिकर्तव्यता अध्वर्यु अधिकृत यजुर्वेद पर निर्भर है। जैसा कि अध्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेता इत्यादि निर्वचनों द्वारा यास्काचार्य्य ने प्रकट किया है। यत की साङ्गोपाङ्गता के लिए ही तत्तद् देवताओं की स्तुति-प्रयोजक ऋचाओं की आवश्यकता हो सकती है और यज्ञ की साङ्गता के लिये हीं गीति-प्रथान ऋचाओं की अपेक्षाकृत जरूरत पड़ती है अत: यज्ञ-प्रक्रिया में सर्वप्रथम यजु: फिर ऋक् और तदनन्तर साम यही क्रम वास्तविक हो सकता है।

क्रमश: ...

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

श्वेता

प्रतिवर्ष, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन, लोग प्राकृतिक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। हर दिन सभी लोगों के छोटे से योगदान से, हम धरती को बचा सकते हैं। यह एक दिन है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह लोगों को सतत जीवन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को साथ आने और परिवर्तन लाने का एक अवसर प्रदान करता है।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझने और जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह दिन हमें ग्रह पर हमारे कार्यों के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में उपाय करने के लिए प्रेरित करता है।

इस अवसर का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजने पर जोर देता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

इसके अलावा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस उन महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो व्यक्ति संरक्षण प्रयासों में निभा सकते हैं। जबकि सरकारें, व्यवसाय और संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी रखते हैं, व्यक्तियों के पास अपने कार्यों के माध्यम से अंतर करने की शक्ति भी होती है।

हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और लुप्तप्राय और विलुप्त होने वाली प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कि पृथ्वी हमारी प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो, हमें प्रकृति वार्तालाप शुरू करने की आवश्यकता है। इस दिन, उन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिन्हें हमें ग्रह को बचाने के लिए करने की आवश्यकता है।

इस तिथि का इतिहास और उत्पत्ति अज्ञात है। हालांकि, समय के साथ, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने हमें पृथ्वी पर होने वाली कमी और प्रदूषण की मात्रा का पता लगाया है। अब समय आ गया है कि हम झुक जाएं और संसाधनों को बचाएं ताकि प्रकृति को हम पर अपना प्रकोप दिखाने से रोका जा सके।

डोनाल्ड के सामने डेमोक्रेट का ट्रंप कार्ड कितना कारगर

अभिनय आकाश

21 जुलाई को जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे थे। नाम वापस लेने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन दिया। इस फैसले की जनाकारी उनके करीबी लोगों और स्टॉफ तक को नहीं था। और तो और कुछ घंटे पहले तक बाइडेन की टीम ये दावा कर रही थी कि वो रेस में बने हुए हैं और उनके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि जो बाइडेन ने अचानक अपनी दावेदारी वापस क्यों ली, कमला हैरिस क्या ट्रंप को हरा सकती हैं और सबसे अहम इन सब का अमेरिका के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?

जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 78 साल की उम्र में इस शपथ के साथ ही वो अमेरिकी इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके कार्यकाल के आखिरी बरस में उनकी उम्र का असर दिखने लगा। जुबान लड़खड़ाने लगे और वो चीजों को भूलने लगे। फिर ये चर्चा तेज हो चली कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कम उम्र होने की वजह से उन्हें अमेरिकी संसद पहुंचने में देरी हुई थी। दरअसल, साल 1972 में बाइडेन ने पहली बार सीनेट का चुनाव जीता। जीतने के दो हफ्ते बाद वो तीस के हुए थे। सीनेटर बनने के लिए कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। जब तक बाइडेन शपथ लेते तभी सड़क हादसे में उनकी बेटी और पत्नी की मौत हो गई। तब बाइडेन ने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें मनाया। फिर 36 सालों तक सीनेट में रहे। दो बार राष्ट्रपति चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। साल 2020 में नॉमिनेशन फाइल किया और फिर ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने। इधर ट्रंप लगातार किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी को प्राइमरी इलेक्शन में कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली। अगस्त के महीने में नेशनल कॉन्वेंशन होने वाला था जिसमें बाइडेन की उम्मीदवारी पर मुहर लगने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही वो पीछे हट

गए। पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 19 अगस्त को है। इसके लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है। चुनाव में अब 105 दिन ही बचे हैं। इसलिए कमला हैरिस ने देशवासियों, खासकर डेमोक्रेट सदस्यों से दो-टूक अपील की, %आइए, हम सभी एकजुट होकर लड़ें, मिलजुल मिलजुल कर चुनाव जीतें।% इस अपील का असर भी हुआ। डेमोक्रेट बहुल कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसम ने उनके समर्थन की घोषणा कर दी। देखते ही देखते कमला हैरिस के समर्थन में एक दर्जन डेमोक्रेट बहुल राज्य और आ गए।

कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इमिग्रेशन और गर्भपात जैसे बड़े मुद्दों पर बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इसके विपरीत डॉनल्ड ट्रंप चार आपराधिक मामलों में कसूरवार और 91 अदालती मामलों अभियुक्त रह चुके हैं। हालांकि ट्रंप को सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग आज भी उनके वैयक्तिक चाल-चलन से नाखुश है। जिन चार राज्यों के गवर्नर चुनावी राजनीति में आगे आना चाहते हैं, वे सभी लोकप्रियता में कमला हैरिस से बहुत पीछे है। इसके बावजूद शीर्षस्थ डेमोक्रेट बराक ओबामा सहित सीनेट और प्रतिनिधि सभा के नेता कमला का समर्थन नहीं कर पाए।

बाइडेन द्वारा हैरिस के समर्थन ने डेमोक्रेट्स को उत्साह से भर दिया है। पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित वरिष्ठ हस्तियों द्वारा उनके लिए समर्थन बढ़ाना इस बात का संकेत है कि पार्टी ने ट्रम्प के खिलाफ जाने के लिए उन पर भरोसा किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अग्रणी उम्मीदवार ने बाइडेन के पीछे हटने के बाद 36 घंटों में दान में 100 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। हैरिस इस दौड़ में सबसे युवा उम्मीदवार हैं क्योंकि बाइडेन की उम्र जैसी चिंता उन पर लागू नहीं होती है। इसके उलट, 78 साल के ट्रंप ही उनसे उम्र में ज्यादा हैं। रिपब्लिकन के खिलाफ वाले लोगों से हैरिस के अभियान को फायदा हो सकता है। द हिल एंड डिसीजन डेस्क मुख्यालय (डीडीएचक्यू) द्वारा बनाए गए वोटिंग पर्सेंट के अनुसार, 53 प्रतिशत अमेरिकी ट्रम्प को अनुकूल रूप से नहीं देखते हैं। फाइव थर्टीआठ मतदान के अनुसार, जो बाइडेन के बाहर होने से पहले आयोजित किया गया था, लगभग 51 प्रतिशत अमेरिकियों ने हैरिस को अस्वीकार कर दिया, जबकि 38 प्रतिशत ने अनुमोदन किया। यह नापसंदगी ट्रंप के लिए अधिक थी, जिन्हें 53 प्रतिशत अमेरिकियों ने पसंद नहीं किया, जबकि 39 प्रतिशत ने उनका समर्थन किया।

गर्भपात का मुद्दा भी हैरिस को ट्रम्प पर बढ़त देता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रो वी वेड को पलटने का एकमात्र श्रेय लिया था। जहां भी गर्भपात के अधिकार मतपत्र पर थे, डेमोक्रेट्स ने राज्य चुनाव जीते हैं, यहां तक ??कि कंसास और केंटकी जैसे रूढ़िवादी राज्यों में भी। ट्रम्प को इसका एहसास हो गया है और उन्होंने गर्भपात के खिलाफ अपनी बयानबाजी कम कर दी है। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हो सकती हैं। उम्मीद की जाती है कि वह प्रजनन अधिकारों को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक बनाएंगी और इस मुद्दे पर ट्रम्प को आड़े हाथों लेंगी। उनका संभावित डेमोक्रेटिक नामांकन भी ऐतिहासिक है क्योंकि वह अमेरिका की पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। यदि वह नवंबर की दौड़ जीत जाती हैं, तो वह एशियाई विरासत की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी।

उपराष्ट्रपति को वह धनराशि भी विरासत में मिली है जो संभावित उम्मीदवार के रूप में पद छोड़ने से पहले जो बिडेन को दान की गई थी। पहली राष्ट्रपति बहस में जो बिडेन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, कई दानदाताओं ने उनके प्रतिस्थापन की मांग की थी और वित्तीय सहायता वापस लेने की धमकी दी थी। यही एक कारण है कि राष्ट्रपति ने अपना चुनाव अभियान खत्म करने का फ़ैसला किया था। पार्टी के कई समर्थकों और स्वयंसेवकों ने 81 मिलियन डॉलर का दान दिया, जिसे छोटे डॉलर का दान बताया जा रहा है। उनकी अभियान टीम को बड़े दानदाताओं से 150 मिलियन डॉलर का दान भी मिला। इसे अमेरिका के इतिहास में 24 घंटे के अंदर मिला अब तक का सबसे ज्यादा दान बताया जा रहा है। कुल 231 मिलियन डॉलर की यह राशि बिडेन द्वारा अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के फैसले के 24 घंटे के भीतर प्राप्त हुई है।

यदि ट्रम्प अलोकप्रिय हैं, तो हैरिस भी अलोकप्रिय हैं। द हिल/डीडीएचक्यू मतदान औसत के अनुसार, हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर ट्रम्प से लगभग 3 प्रतिशत अंक पीछे हैं। औसत से पता चलता है कि उनकी अस्वीकृति रेटिंग 56 प्रतिशत थी, जबकि केवल 38 प्रतिशत अमेरिकियों ने उन्हें अनुकूल रूप से देखा था। जैसा कि द हिल ने कहा, इसका मतलब यह है कि उनकी उम्मीदवारी के लिए डेमोक्रेटिक उत्साह ज़मीनी मतदाताओं के बीच दोहराया नहीं गया है। एक महिला राष्ट्रपति, वह भी एक अश्वेत महिला, को चुनने के प्रति मतदाताओं का पूर्वाग्रह, हैरिस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

आज का इतिहास

1878 बर्लिन सम्मेलन के समापन पर रुस जर्मनी, फ़्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के बीच बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
1914 आस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यहां से प्रथम विश्वयुद्ध की शुरूआत हुई।
1914 आस्ट्रिया-हंगरी ने सर्जेवो में आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद जुलाई अल्टीमेटम के केवल भाग के सर्बिया की शर्त स्वीकार करने के बाद युद्ध की घोषणा की।
1932 अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने बोनस आर्मी के निष्कासन का आदेश दिया-उन दिग्गजों का एक समूह, जो पैसे की अदायगी के लिए तत्काल भुगतान की मांग करने के लिए सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे।
1935 बोइंग बी-17 फ्लाइंग किले भारी बमवर्षक विमान, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में किसी अन्य अमेरिकी विमान की तुलना में अधिक बम गिराए, ने पहली उड़ान भरी।
1957 जापान के इशहाया में भारी बारिश की वजह से 992 लोगों की मौत हुई।
1959 ग्रेट ब्रिटेन में डाक कोड का प्रयोग शुरु हुआ।
1976 रिक्टर पैमाने पर कम से कम 8.2 तीव्रता का भूकंप, जो इतिहास में सबसे घातक है, चीन के तांगशान में फैल गया, जिसमें कम से कम 2,40,000 लोग मारे गए।
1977 ट्रांस-अलास्का पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से पहला तेल वाल्डेज़, अलास्का पहुंचता।
1978 सोवियत संघ ने पूर्वोत्तर कजाखस्तान में परमाणु परीक्षण किया।
1983 नासा ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह टेल्सटार-3ए का प्रक्षेपण किया।
1989 ब्रेव्स डेल मर्फी ने एक पारी में 2 3 रन की घरेलू पारी खेली। वह एक पारी में 2 घरेलू रन बनाने वाले 14 वें व्यक्ति हैं। उन्होंने एक पारी में 6 आरबीआई का रिकॉर्ड भी बनाया है।
1990 अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू के राष्ट्रपति बने।
1995 संयुक्त राज्य अमेरिका के अटार्नी की डिस्ट्रिक्ट ऑरेगॉन की हत्या के लिए भगवान श्री रजनीश के दो अनुयायियों को दोषी ठहराया गया था।
1995 ओशो के दो अनुयायियों (भगवान श्री रजनीश) को ओरेगन के रजिस्ट्रार के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी की हत्या का दोषी ठहराया गया था।
1996 प्रागैतिहासिक केनेविक मैन के अवशेषों की खोज अमेरिका के वाशिंगटन, केनेविक के पास कोलंबिया नदी के ओना बैंक में की गई थी।
1998 लेविंस्की और स्टार ने लेविंस्की और उसके माता-पिता के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा समझौते की घोषणा की। इसे महीनों के सत्ता संघर्ष के बाद बनाया गया था।

किसान आंदोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

ललित गर्ग

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की

कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है।

विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगें राजनीतिक मुद्दे बन गये हैं, जिनके चलते हो रहा आन्दोलन न केवल किसानों के बल्कि आम जनता के लिये भी परेशानी का सबब है। जबकि सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा कर 2300 कर दिया है जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी की सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई है। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। विपक्षी दल किसानों के हित में आन्दोलन की बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। स्तरीय विरोध हो, किसानों को गुमराह करने एवं उनका मनोबल कमजोर करने के लिये विपक्षी दल उजालों पर कालिख न पोते, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं है।

कांवड़ः तब और अब के बीच का अंतर

सुरेश पंत

कहा जाता है कि भगवान शिव को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि व्याकुल हो गयी। भगवान शंकर ने स्वयं विष पीकर लोगों को संकट से मुक्त किया। इतना अधिक गरल पान करने से जब शिव भी बेचैन होने लगे, तो कहा जाता है कि शिव जी के परम भक्त रावण ने गंगाजल से उनका अभिषेक किया, ताकि विष के प्रभाव की तीव्रता कम हो सके। लोक मान्यताओं के अनुसार, आज उस पौराणिक शिवालय की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 'पूरा महादेव' के रूप में की जाती है, जो रावण की ससुराल के निकट है। आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां जल चढ़ाने आते हैं। जब किसी शिवलिंग पर जलाभिषेक भक्ति प्रदर्शन से अधिक, व्यक्तिगत आस्था का विषय था, तब भी भक्तों द्वारा गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार (उत्तराखंड), अजगैबीनाथ, सुल्तानपुर (भागलपुर, बिहार) से गंगाजल लेकर काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ धाम तथा अन्य छोटे-बड़े स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करने का रिवाज रहा है। सावन महीने को शिव के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए सावन में गंगाजल से जलाभिषेक करने का विशेष रिवाज है। यह मानने के कारण हैं कि यद्यपि कांवड़ यात्रा का चलन कम से कम तीन-चार सौ वर्ष पुराना रहा होगा, किंतु इतने विशाल उत्सव मेले के रूप में मनाने का चलन 25 से 30 वर्ष पुराना होगा। मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूं। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। मैं रामेश्वरम की यात्रा पर था, तो रेलगाड़ी में मेरे एक सहयात्री कोई दंडी स्वामी थे, जो मदुरै से रामेश्वरम जाने वाली गाड़ी में हमारे डिब्बे में आ गये थे। स्वामी जी ने बताया कि अवकाश प्राप्ति से पहले वे बिहार की किसी अदालत में न्यायाधीश थे। अब गोमुख से गंगाजल लेकर रामेश्वरम शिवलिंग में अभिषेक करेंगे। रामेश्वरम में दर्शनार्थियों की कतार में जब उनकी बारी आयी, तो पुरोहित ने उन्हें स्वयं जल चढ़ाने से मना कर दिया, यह कहकर कि आम दर्शनार्थियों को लिंग तक जाने की अनुमति नहीं है, वे गंगाजली (लोटा) उन्हें दे दें, 'मैं आपकी ओर से जल चढ़ा दूंगा।' स्वामी जी का कहना था कि गोमुख से जल लेकर हजारों मील की यात्रा करके मैं आया हूं, अब जब केवल पांच-छह कदम की दूरी रह गयी है, तो यह काम आपको कैसे सौंप सकता हूं। मेरे और मेरे शिव के बीच कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। बीच-बचाव के बाद उन्हें इतना निकट आने दिया गया कि वे जल चढ़ा सकें। वर्ष 1960, 70 व 80 के वर्षों में भी दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार मार्ग में कांवरियों के इक्का-दुक्का झुंड कहीं मिल जाते थे, परिवहन बिना किसी बाधा के चलता रहता था। आइए कांवड़, कांवरिया शब्दों की व्युत्पत्ति पर एक दृष्टि डालें। 'कांवड़' मूलतः वह बांस है, जिसके दोनों सिरों पर भार ढोने के लिए दो छींके लटके होते हैं। कांवड़ के सिरों पर भार को संतुलित कर बांस को कंधे पर रखकर ढोया जाता है। समूचे उपकरण का नाम कहीं बहंगी भी है, जिसे कांवड़ भी कहा जाता है। कांवरिया का संबंध इसी कांवड़ शब्द से है। कांवड़ की व्युत्पत्ति सत्संग-प्रवचन शैली में तीर-तुक्के मिलाकर अनेक प्रकार से दी जाती है, पर लगता है इसका संबंध संस्कृत के कर्पट, कर्पटिक, कार्पटिक शब्दों से है। संस्कृत में 'कर्पट' फटा, थेगली लगा कपड़ा है और 'कर्पटिक' ऐसे कपड़ों वाला। गूदड़ी (कंथा) थेगलियों की ही होती थी जो यात्रियों के लिए जरूरी सामान थी। बहंगी (कांवड़) के सिरों पर लटकते पल्ले भी थेगलियों से मढ़े होते थे।

भाजपा-आरएसएस : 'परिवार' में फिर से कैसे कायम हो शांति?

हरीश गुप्ता

इस साल मई में लोकसभा चुनाव के बीच शुरू हुए भाजपा और उसके संरक्षक आरएसएस के बीच कड़वे अध्याय का अभी उपसंहार नहीं हुआ है। 'संघ परिवार' में इस तरह के मतभेद कोई नई बात नहीं हैं, क्योंकि वसंतराव ओक, बलराज मधोक, लालकृष्ण आडवाणी या यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ये मतभेद सामने आए थे। लेकिन ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह इनका अंत हमेशा सुखद होता था और आरएसएस हमेशा विजयी होता था। लेकिन इस बार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 मई 2024 को कुछ ऐसा कह दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी।

लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने कहा कि भाजपा को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है और (अपने मामलों को खुद चलाने में) सक्षम है। वह यहीं नहीं रुके और आगे कहा, ''हर किसी की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां और भूमिकाएं हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन हैं।।। यह जरूरत का सवाल नहीं है।।।।''

नड्डा के बयान ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों और परिवार को चौंका दिया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। हालांकि, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा नेतृत्व को चौंका दिया क्योंकि उसकी सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 पर आ गई। पार्टी ने बहुमत खो दिया, हालांकि एनडीए विजेता बनकर उभरा। उम्मीद थी कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में कुछ सुधार करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

आखिरकार, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ठीक दो महीने बाद 18 जुलाई को बोलने का फैसला किया। उन्होंने रांची में एक सार्वजनिक समारोह में कहा, ''आत्म-विकास के क्रम में, एक व्यक्ति पहले 'सुपरमैन' बनना चाहता है, फिर 'भगवान' और फिर 'विश्वरूप'। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लक्षित व्यक्ति के बारे में किसी को संदेह नहीं रहा।

अब सबकी निगाहें केरल में 31 अगस्त से शुरू हो रही आरएसएस की तीन दिवसीय वार्षिक समन्वय समिति की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें भाजपा समेत इसके सभी 36

अग्रणी संगठनों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अंदरूनी सूत्रों को उम्मीद है कि केरल बैठक में नड्डा और कुछ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने से आगे का रास्ता निकल सकता है।

खबरों की मानें तो भाजपा नेतृत्व पहले ही सुलह के पक्ष में है। पार्टी को एहसास हो गया है कि आरएसएस के बिना वह 'नई कांग्रेस' बन जाएगी। अगर आरएसएस हर जिले और कस्बे में अपनी राजनीतिक शाखा से अपने कार्यकर्ताओं को हटा लेता है, तो भाजपा के पास केवल दूसरे दलों से आए दलबदलू ही बचेंगे।

चिंतित भाजपा सरकार मंत्रिमंडल गठन में व्यस्त थी और खबर है कि उसने रास्ता निकालने के लिए आरएसएस के दिग्गज सुरेश सोनी के दरवाजे खटखटाए हैं। सोनी का आरएसएस में काफी सम्मान है और उन्होंने गुजरात में काम किया है और मोदी को दिल्ली लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

आरएसएस नेतृत्व ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रॉक्सी या किसी और तरीके से सरकार चलाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। हालांकि, वह चाहेगा कि नए पार्टी प्रमुख की नियुक्ति से पहले उससे सलाह ली जाए, जो आरएसएस का समर्पित कार्यकर्ता हो। भाजपा ने जवाब में कहा कि बजट सत्र के कारण समय कम है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिसके लिए समय देना होगा।

यह भी कहा गया कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। इस बीच कई नाम सामने आए, जिनमें महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने सुझाव दिया कि नड्डा को जनवरी 2025 तक पार्टी पद पर बने रहने दिया जाए।

हालांकि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, जो पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर हैं, दिल्ली में तैनात हैं और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार भाजपा के साथ समन्वय का काम देखते हैं, लेकिन इस संकट को सुरेश सोनी ने संभाला।

मनोहर लाल खट्टर ने भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और करनाल से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे उनके राज्य में कामकाज चलाने पर रोक नहीं लगी है। वे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बंगले में ही रह रहे हैं, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी नायब सिंह सैनी को प्रशासन चलाने में उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

खट्टर मोदी के वफादार हैं और पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता हैं। उनके कहने पर ही खट्टर के एक और वफादार मोहन लाल बडोली को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बडोली ने सोनीपत से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे असफल रहे। वे भाजपा के विधायक हैं।

वे जाति से ब्राह्मण हैं और भाजपा को उम्मीद है कि राज्य में गैर-जाट वोटों के बहुमत को अपने पाले में ला सकेंगे। खट्टर पंजाबी हैं, जबकि सैनी ओबीसी हैं। भाजपा को लगता है कि जाट कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी में बंट जाएंगे। हालांकि, भाजपा को तीसरी बार किस्मत आजमाने में मुश्किल होगी।

लोकसभा चुनावों के दौरान, भाजपा को राज्य में बड़ा झटका लगा था जब उसने 10 में से पांच लोकसभा सीटें खो दीं और उसका वोट प्रतिशत भी गिर गया। कई लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि खट्टर हरियाणा में पार्टी का चेहरा क्यों बने हुए हैं, जबकि दिसंबर में विधानसभा चुनावों से पहले सत्ता विरोधी लहर के कारण उन्हें हटा दिया गया था।

विस चुनाव से पहले ही अलग हो जाएंगे अजित और भाजपा!

आशीष तिवारी

अगले कुछ महीनो में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता वापसी के लिए वर्तमान सरकार एड़ी से चोटी का जोर भी लगा रही है। लेकिन इस जोर में एक कमजोर कड़ी भी सामने दिख रही है। दरअसल वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार में अजित पवार की एनसीपी को लेकर कई तरह के सियासी संशय सामने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में कहा यह तक जा रहा है की सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार फंस रहे पेंच पर संभव है अजित पवार की एनसीपी विधानसभा के चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरे। हालांकि इन सभी सियासी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। दो दिन पहले ही अजित पवार ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उसके बाद पार्टी की बैठक में शामिल होकर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर विधानसभा चुनाव में सियासी संभावनाओं पर चर्चा की।

दरअसल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम में अजित पवार की एनसीपी का जो रिजल्ट रहा उससे गठबंधन में अजित पवार को रखा जाए या ना रखा जाए इसको लेकर सवाल उठने लगे। हालात ऐसे हो गए की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों ने भी अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के हुए गठबंधन पर सवालिया निशान उठा दिए। सियासी जानकारों का भी मानना है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी है उसमें अजित पवार के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीटों पर समझौते को लेकर कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शितोले कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही

है उसमें अजित पवार की पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

दरअसल 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर 160 से 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो बची हुई 120 से 130 सीटों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को हिस्सेदारी मिलेगी। जबकि महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की हो रही है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियां भी सौ सौ सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मामला आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही सियासी पेंच को दूर करने के लिए अजित पवार की ओर से पार्टी की बैठको में चर्चाएं की जा रही है। हाल में ही अजित पवार ने एक बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आने वाले निकाय चुनाव में उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजित पवार का निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला विधानसभा के चुनावों के नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में अजित पवार की पार्टी से 40 विधायक इस वक्त है।

महाराष्ट्र की इसी सियासी उधेड़बुन के बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार दो दिन पहले दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई।राजनीतिक विश्लेषक सुमित चंद्रभाऊ वडवालकर कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस मुलाकात के बाद कहा यह जाने लगा की सीटों के बंटवारे पर बहुत हद तक फैसला हो चुका है। क्योंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे। वडवालकर का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से पेंच फंसा है उससे यह बिल्कुल नहीं लगता है कि अजित पवार बहुत कम सीटों पर मानने वाले हैं। वह भी तब जब सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अजित पवार से कम विधायकों वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी को उनसे ज्यादा सीटें दी जा सकती है। वही अजित पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि उनकी पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें।

दरअसल अजित पवार को लोकसभा चुनाव में दी गई सीटों के परिणाम पक्ष में नहीं आए। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं भी हुईं। कहा यह तक गया कि महाराष्ट्र में अजित पवार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में कोई सियासी लाभ नहीं हुआ। जबकि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के सांसद भी ज्यादा बने। इसी गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारको ने भी सवाल उठाए हैं। इन सवालों के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में कहा यह जा रहा है कि अगर आने वाले विधानसभा के चुनावों से पहले अजित पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं के मंशा अनुरूप समझौता नहीं होता है तो सियासी राहें भी अलग हो सकती है। जिस तरीके से निकाय चुनाव में एनसीपी ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही है उससे बहुत कुछ स्पष्ट भी हो रहा है। हालांकि अजित पवार की ओर से आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिल बैठकर सीटों के बंटवारे वाले फार्मूले पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं।

विपक्षी नेता दूसरों के बोलने का अवसर क्यों छीनना चाहते हैं?

नीरज कुमार दुबे

नीति आयोग की बैठक का विपक्ष शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक का बहिष्कार तो नहीं किया लेकिन इसमें शामिल होने से पहले ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वह विरोध जताकर आयेंगी। ऐसा उन्होंने किया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। देखा जाये तो विपक्ष के नेता आजकल माइक बंद करने का आरोप धड़ल्ले से लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि संसद की कार्यवाही हो या अन्य कोई सरकारी बैठक, उसमें भाग लेने वालों के लिए कुछ नियम हैं। सबके लिए समय आवंटित करने और कौन कितना समय बोलेगा इसका निर्धारण करने के लिए भी पहले से नियम बने हुए हैं। यदि कोई निर्धारित अवधि से ज्यादा समय बोलेगा तो जाहिर है कि यह दूसरों के अधिकारों का हनन होगा। देखा जाये तो नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी भले कुछ भी आरोप लगायें, मगर सच यह है कि उनके आग्रह पर उन्हें उनके निर्धारित समय से पहले ही बोलने का अवसर दिया गया। उनके भाषण का समय खत्म होने का इशारा घड़ी ने किया और भाषण खत्म करने का संकेत देने वाली बेल भी उनके लिए नहीं बजायी गयी। इसके अलावा, जो मुख्यमंत्री अपने राज्य के साथ भेदभाव करने का केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं यदि वह यूपीए और एनडीए शासन के दौरान अपने राज्य को मिली केंद्रीय मदद पर एक श्वेतपत्र ले आयें तो हकीकत उन्हें भी पता चल जायेगी और सारी स्थिति जनता के समक्ष भी आ जायेगी। केंद्र पर अपने राज्य से भेदभाव का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्रियों को यह भी बताना चाहिए कि उनकी किन मांगों को अनसुना कर दिया गया? इन मुख्यमंत्रियों को यह भी बताना चाहिए कि अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये और उनका क्या परिणाम रहा? वैसे, ममता बनर्जी ने बैठक से बीच में ही बाहर आकर जो आरोप लगाये हैं उससे यह भी प्रदर्शित होता है कि यह सब इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम था। दरअसल विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का निर्णय किया था तब उन राज्यों में विपक्ष और जनता ने सवाल उठाया था कि जब प्रधानमंत्री के समक्ष अपने राज्य की मांगों को सीधा रखने का अवसर मिला है तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा? ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश की जनता की नजरों में नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के निर्णय को सही ठहराने के लिए ममता बनर्जी को भेजा। ममता बनर्जी से गलती सिर्फ इतनी हो गयी कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह बैठक में विरोध जताएंगी। इसलिए जब वह बाहर आकर केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहीं हैं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा। वैसे रणनीति के मुताबिक, विपक्ष ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा किया जायेगा। इसलिए संसद के वर्तमान सत्र के दौरान विपक्ष का और उग्र रूप देखने को मिल सकता है। बहरहाल, यह साफ प्रदर्शित हो रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में जनता ने विपक्ष को जो ताकत दी है उसका वह सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। सिर्फ हंगामे की राजनीति और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का खेल चल रहा है।

आज की आवश्यकता
सब्जी बगीचा

अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक आहार में संतुलित पोषण का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। फल एवं सब्जियाँ इसी संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है क्योंकि ये विटामिन, खनिज लवण तथा कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर भी ये जरुरी हैं कि इन फल एवं सब्जियों की नियमित उपलब्धता बनी रहे. इसके लिए घर के पिछवाडें मे पडी जमीन पर खेती करना बहुत ही लाभदायक उपाय हैं। पोषाहार विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम फल और 300 ग्राम साग–सब्जियों का सेवन करना चाहिए। परन्तु हमारे देश में साग–सब्जियों का वर्त्तमान उत्पादन स्तर प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति की खपत के हिसाब से मात्र 120 ग्राम है।

सब्जी बगीचा

- उपलब्ध स्वच्छ जल के साथ रसोईघर एवं स्नानघर से निकले पानी का उपयोग कर घर के पिछवाड़े में उपयोगी साग-सब्जी उगाने की योजना बना सकते हैं।
- एकत्रित अनुपयोगी जल का निष्पादन हो सकेगा और उससे होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिल जाएगी।
- सीमित क्षेत्र में साग-सब्जी उगाने से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति भी हो सकेगी।
- सब्जी उत्पादन में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं होगी।

अतः यह एक सुरक्षित पद्धति है तथा उत्पादित साग-सब्जी कीटनाशक दवाईयों से भी मुक्त होंगी।

सब्जी बगीचा के लिए स्थल

सब्जी बगीचा के लिए स्थल घर का पिछवाड़ा ही होता है जिसे हम लोग बाड़ी भी कहते हैं। यह सुविधाजनक स्थान होता है क्योंद्धक परिवार के सदस्य खाली समय में साग-सब्जियों पर ध्यान दे सकते हैं तथा रसोईघर व स्नानघर से निकले पानी आसानी से सब्जी की क्यारी की ओर घुमाया जा सकता है। सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता और व्यक्तियों की संखया पर निर्भर करता है। चार या पाँच व्यक्ति वाले औसत परिवार के लिए 1/20 एकड़ जमीन पर की गई सब्जी की खेती पर्याप्त हो सकती है।

पौधा लगाने के लिए खेत तैयार करना

सर्वप्रथम 30-40 सेंमी की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से जुताई करें। खेत से पत्थर, झाड़ियों एवं बेकार के खर-पतवार को हटा दें। खेत में अच्छे ढंग से निर्मित 100 कि.ग्राम कृमि खाद चारों ओर फैला दें। आवश्यकता के अनुसार 45 सेंमी या 60 सेंमी की दूरी पर मेड़ या क्यारी बनाएँ।

सब्जी बीज की बुआई और पौध रोपण

सीधे बुआई की जाने वाली सब्जी जैसे -भिंडी, पालक एवं लोबिया आदि की बुआई मेड़ या क्यारी बनाकर की जा सकती है। दो पौधे 30 सेंमी की दूरी पर लगाई जानी चाहिए। प्याज, पुदीना एवं धनिया को खेत के मेड़ पर उगाया जा सकता है।प्रतिरोपित फसल, जैसे - टमाटर, बैगन और मिर्ची आदि को एक महीना पूर्व में नर्सरी बेड या टूटे मटके में उगाया जा सकता है। बुआई के बाद मिट्टी से ढ़ककर उसके ऊपर 2सब्जी बगीचा का मुखय उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तथा वर्ष भर घरेलू साग-सब्जी की आवश्यकता की पूर्ति करना है। बगीचा के एक छोर पर बारहमासी पौधों को उगाया जाना चाहिए जिससे इनकी छाया अन्य फसलों पर न पड़े तथा अन्य साग-सब्जी फसलों को पोषण दे सकें। बगीचा के चारों ओर तथा आने-जाने के रास्ते का उपयोग विभिन्न अल्पावधि हरी साग-सब्जी जैसे - धनिया, पालक, मेथी,पुदीना आदि उगाने के लिए किया जा सकता है।

50 ग्राम नीम के फली का पाउडर बनाकर छिड़काव किया जाता है ताकि इसे चीटियों से बचाया जा सके। टमाटर,गोभी, बैगन, मिर्ची के लिए 25-30 दिनों की बुआई के बाद तथा प्याज के लिए 40-45 दिनों के बाद पौधे को नर्सरी से निकाल दिया जाता है।टमाटर, बैंगन और मिर्ची को 30-45 सेंमी की दूरी पर मेड़ या उससे सटाकर रोपाई की जाती है। प्याज के लिए मेड़ के दोनों ओर रोपाई की जाती है। रोपण के बाद पौधों की सिंचाई की जाती है।

फसल चक्र

वर्षा, शरद और ग्रीष्म की फसलें तालिका में बतलाए अनुसार लेना चाहिए -

वर्ष भर उगाने के लिए फसल चक्र

खरीफ	रबी	जायद	खरीफ	रबी	जायद
पालक	मिर्च	ककडी	बैंगन	मूली	भण्डी
तरोई	लहसून	छप्पन कद्दू	लोबिया	आलू	कद्दू
टमाटर	मैथी	तरबूज	मूली	प्याज	धनिया
टिण्डा	मटर	टमाटर	प्याज	पालक	करेला
भिण्डी	पत्तागोभी	करेला	भिण्डी	मूली	तरोई
लौकी	आलू	खरबूज	धनिया	फूलगोभी	लौकी
फूलगोभी	धनिया	प्याज	पुदीना	पुदीना	पुदीना
मिर्च	बाकला	टिण्डा	केला	केला	केला
ग्वार	बैंगन	बैंगन	नींबू	नींबू	नींबू
मिर्च	गाजर	पालक	पपीता	पपीता	पपीता

उत्तर भारत में खरीफ मौसम में प्याज की खेती

उत्तरी भारत में प्याज रबी की फसल है यहां प्याज का भंडारण अक्टूबर माह के बाद तक करना सम्भव नही है क्योकि कंद अंकुरित हो जाते हैं।

इस अवधि(अक्टूबर से अप्रैल) में उत्तर भारत में प्याज की उपलब्ध्ता कम होने तथा परिवहन खर्चे के कारण दाम बढ जाते हैं। इसके समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तर भारत के मैदानो में खरीफ में भी प्याज की खेती के लिए एन-53(ह्र-53) तथा एग्रीफाउंड डार्क रैड नामक प्याज की किस्मों का विकास किया है।

प्याज की किस्म - एन-53(आई.ए.आर.आई.); एग्रीफाउंड डार्क रैड (एन.एच.आर.डी.एफ.)

बीज बुआई समय - मई अंत से जून

रोपाई का समय - मध्य अगस्त

कटाई - दिसम्बर से जनवरी

पैदावार - 150 से 200 क्विंटल/हैक्टेयर

अरहर में रोग प्रबंधन

अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है । दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। अरहर अंतर फसल एवं बीच के फसल के रूप में उगाई जाती है, अरहर ज्वार, बाजरा, उर्द एवं कपास के साथ बोई जाती है ।अन्य फलों की तरह अरहर में भी रोग का प्रकोप होता है जिनमें से कुछ रोगों के संक्षिप्त विवरण एवं प्रबंधन नीचे दर्शाया गया है ।

उकठा रोग (विल्ट)

यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है । इस रोग में पौधा पीला पड़कर सुख जाता है । फसल में फूल एवं फल लगने की अवस्था में एवं बारिश के बाद इस रोग का प्रकोप अधिक होता है । रोग ग्रसित पौधों की जडें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं । एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर इस रोग की उग्रता बढती है ।

उकठा रोग (विल्ट)

प्रबंधन –

- जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3-4 साल तक अरहर की फसल न लें ।
- खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें ।
- ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है।
- कवक नाशी जैसे बेनोमील 50त्न + थायरम 50त्न के मिश्रण का तीन ग्राम प्रति किलो बीज की डर से उपचारित करें ।
- ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं ।
- रोग रोधी किस्में आशा, राजीव लोचन, सी -11 आदि का उपयोग बुआई हेतु करें ।

अरहर का बाँझ रोग -

यह रोग विषाणु जनित है जिसका वाहक एरियोफिड माईट है जो की एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। इस रोग की अधिकता के कारण 75% तक उत्पादन में कमी देखी गयी है । रोग से ग्रसित पौधे पीलापन लिए हुए झाड़ीनुमा हो जाते हैं । पत्तियों के आकार में कमी, शाखाओं की संख्या में वृद्धि तथा पौधों में आंशिक या पूर्ण रूप से फूलों का नहीं आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। फूल नहीं आने से फल नहीं लगते इसलिए इस रोग को बाँझ रोग कहते हैं । फसल पकने की अवस्था में रोगी पौधे लम्बे समय तक हरे दिखाई देते हैं जबकि स्वस्थ पौधे परिपक्व होकर सूखने लगते हैं ।

अरहर का बाँझ रोग -

प्रबंधन-

- जिस खेत में अरहर लगाना हो उसके आसपास अरहर के पुराने एवं स्वयं उगे हुए पौधे नष्ट कर देना चाहिए।
- खेत में जैसे ही रोगी पौधे दिखे उनको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
- फसल चक्र अपनाना चाहिए।
- रोग रोधी प्रजातियाँ जैसे- पूसा-9, आई.सी.पी.एल.-87119, राजीव लोचन, एम.ए.-3, 6, शरद आदि का चयन करना चाहिए।
- फयूराडान 3 जी., की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की डर से उपचारित करना चाहिए एवं फसल की प्रारंभिक अवस्था में कैल्थेन (1 मिली./ली. पानी) का छिड़काव रोगवाहक माईट के रोकथाम में प्रभावी होता है ।

तना अंगमारी रोग (स्टेम ब्लाइट)-

यह रोह कवक के द्वारा होता है। इसका प्रकोप । दिन से लेकर एक माह के पौधों में दिखाई देता है । शीघ्र पकने वाली किस्मों में इस रोग का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है । प्रभावित पौधों की पत्तियों पर पनीले धब्बे बन जाते हैं एवं एक सप्ताह के भीतर पूरी पत्तियां जलकर नष्ट हो जाते हैं । साथ ही तने एवं शाखाओं पर धब्बे गोलाई में बढ़कर उतने भाग को सुखा देते हैं, जिससे तना एवं शाखाएं टूट जाती हैं । इस रोग का प्रकोप कम उम्र के पौधों में अपेक्षाकृत अधिक होता है। अनुचित जल निकास वाले क्षेत्रों में भी इस बीमारी का प्रभाव अधिक होता है ।

तना अंगमारी रोग (स्टेम ब्लाइट)-

प्रबंधन -

- बीजों को बुवाई से पूर्व रिडोमिल नामक कवकनाशी की 2 ग्रा. मात्रा प्रति किग्रा.बीज की से उपचारित करें ।
- खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें ।
- जहाँ इस रोग का प्रकोप अधिक होता है वहां 3-4 वर्ष तक अरहर की फसल नहीं लेनी चाहिए ।
- रोग की प्रारभिक अवस्था में ताम्रयुक्त कवकनाशी जैसे फायटोलान 50त्न की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से या रिडोमिल एम.जेड. 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से 10-12 दिन के अन्तराल में छिड़काव करना चाहिए ।
- रोगरोधी किस्में जैसे :- पूसा-9, एन.ए.-1, एम.ए.-6, बहार, शरद, अमर आदि का चुनाव करना चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नीति आयोग की बैठक में नहीं आए बिहार के सीएम नीतीश

पटना। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही नीति आयोग की बैठक को लेकर राजनीति खूब हो रही है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की ओर से इसका बहिष्कार किया गया है। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसको लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। महत्वपूर्ण बैठक से नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण तत्काल पता नहीं चल सका है। नीति आयोग, जो केंद्र सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल (एलजी) और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में हिस्सा लेने और अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए पीएम मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया है।

नीति आयोग की बैठक छोड़ निकलीं ममता बनर्जी

नईदिल्ली। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई थीं। लेकिन उन्होंने ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए बैठक छोड़ दिया है। ममता ने दावा किया कि मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की। विपक्ष से मैं अकेली थी जो भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद हो गया। मैंने कहा आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए बजाय इसके कि आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार को अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं, यह सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान है।

ममता बनर्जी के दावे पर सरकार ने दी सफाई

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह दावा करते हुए बाहर चली गईं। कि उनका माइक म्यूट कर दिया गया था और उन्हें पांच मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी गई। इस बीच, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि यह दावा भ्रामक है। घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक कि इसे चिह्नित करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। इस बीच, बीजेपी ने बनर्जी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ लोगों ने नीति आयोग को बहिष्कार का मंच बना लिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बनर्जी हर मंच पर हर चीज का विरोध करने की राजनीति के जरिये राजनीतिकरण करने की कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा में हैं। बनर्जी ने पहले कहा था कि अगर उन्हें वहां अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी गई तो वह बैठक छोड़कर चली जाएंगी।

ब्रजेश पाठक-केशव मौर्य पर क्या गिरेगी गाज?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की कार्यसमिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कहीं उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें।

भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर भड़के शरद पवार

मुंबई। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उनके बयान को लेकर पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने बीते दिनों अपने एक बयान में शरद पवार को राजनीति में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अब शरद पवार ने अमित शाह पर पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से बाहर किया गया था, वो देश का इतना अहम मंत्रालय संभाल रहा है। शरद पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे खिलाफ बयान दिया था और कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। हैरानी है कि एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, जिसे कानून के गलत इस्तेमाल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर कर दिया था! एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार ने कहा जिस व्यक्ति को निर्वासित किया गया था, वो आज देश का गृह मंत्री है।

नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी राज्यों के संयुक्त प्रयासों से %विकसित भारत 2047% का सपना हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने 100 साल में एक बार आने वाली महामारी को हरा दिया है। हमारे लोग उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हैं। हम सभी के संयुक्त प्रयास से विकसित भारत 2047 के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राज्य विकसित राज्य बनाएंगे। बैठक के बाद नीति आयोग द्वारा साझा किए गए एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को

नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह बदलावों, तकनीकी और भू-राजनीतिक और अवसरों का दशक है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रगति की सीढ़ी है। नीति आयोग केंद्र का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के सहयोगी हैं, और कई विपक्षी मुख्यमंत्री शनिवार को बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुईं, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए बाहर चली गईं कि जब उन्होंने पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। लेकिन, सरकारी सूत्रों ने उनके दावे का खंडन करते हुए कहा कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था और उनकी बारी दोपहर के भोजन के बाद आती।

बंगाल में अराजकता और अघोषित आपातकाल : अधीर रंजन

कोलकाता। लोकसभा चुनाव में हार को अभी दो महीने भी नहीं बीते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने शिकायत की कि बंगाल में अराजकता चल रही है। कृत्रिम रूप से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने बयान में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव हो या न हो, हमें बंगाल में एक तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। जबरदस्ती चुनाव जीतते हैं

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, इसलिए कुछ जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरन मारपीट या रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है। अगर कोई उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो उन्हें मार दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जलपाईगुड़ी में हमारे कार्यकर्ता को पेड़ से बांधकर बेरहमी से मार दिया गया। पूर्व सांसद ने आगे कहा कि ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं तो संत बन जाती हैं लेकिन बंगाल में उनकी पार्टी शैतान हो जाती है। बहरामपुर के पूर्व सांसद ने शिकायत की कि चुनाव आयोग के सख्त कदमों के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल के आतंक को रोका नहीं जा सका। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात चुनाव के बाद हुई हिंसा है. अधीर का दावा है कि बंगाल के विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने जीवन और आजीविका को लेकर संशय में हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मैनागुड़ी में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र किया. अधीर का दावा है कि राज्य में इस वक्त अघोषित आपातकाल चल रहा है. जिससे निपटने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

इरादे साफ हैं तो ओबीसी आरक्षण बिल पास करें

नईदिल्ली। आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा और सत्तारूढ़ दल पर दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों के खिलाफ है और अगर यह ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें बिल पास करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और हम इस बिल का एक बार नहीं बल्कि 1000 बार समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपकी पार्टी और आपकी नियत साफ है तो इससे अच्छा कोई बिल नहीं आ सकता।

रेवंत रेड्डी ने लगाया केसीआर की पार्टी पर करोड़ों की लूट का आरोप

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर अपने कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए आवंटित करोड़ों रुपये लूटने का आरोप लगाया और कृषि पंप-सेटों पर मीटर लगाने के बारे में गलत बयान देने के लिए टी हरीश राव पर हमला किया। तेलंगाना विधानसभा में बोलते हुए, रेड्डी ने बीआरएस नेता टी हरीश राव की इस टिप्पणी पर तीखा खंडन किया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को पूरा न करके राज्य को धोखा दिया है। रेड्डी ने कहा कि हरीश राव का भाषण झूठ से भरा है। लोग विपक्षी दल पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों ने बीआरएस के खिलाफ जनादेश दिया और उन्हें सार्वजनिक अदालत में दंडित किया। विपक्ष ने इससे सीख नहीं ली है और गलत बयान दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीआरएस शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार के उदाहरणों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 7,000 करोड़ रुपये की मामूली राशि के लिए आउटर रिंग रोड की बिक्री भी शामिल थी।

रूस के बाद यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। यूक्रेन में शांति कायम करने के नये वैश्विक प्रयासों के बीच भारत और पूर्वी यूरोपीय देश अगले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र की कीव यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। राजनयिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोदी 24 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस के आसपास कीव की यात्रा कर सकते हैं और उनके यूक्रेन से पोलैंड जाने की भी संभावना है।

प्रधानमंत्री ने इटली के अपुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन के इतर पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। अगर मोदी पोलैंड जाते हैं, तो यह चार दशक से

अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा होगी।

सूत्रों ने बताया कि भारत और यूक्रेन अगस्त में मोदी की कीव यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी यात्रा पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके लिए व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता होगी।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की दो देशों की यह यात्रा 23-24 अगस्त के आसपास शुरू हो सकती है। हालांकि, भारत या यूक्रेन की ओर से अभी यात्रा की संभावनाओं पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि भारत, रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने साधनों के भीतर हरसंभव प्रयास करना जारी रखेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि शांति का रास्ता ''बातचीत और कूटनीति'' से होकर गुजरता है। मोदी ने जेलेंस्की से कहा था कि भारत ''मानव-केंद्रित'' दृष्टिकोण में विश्वास करता है। उस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को कीव की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था।

भारत यह कहता रहा है कि यूक्रेन में संघर्ष को संवाद और कूटनीति के जरिये हल किया जाना चाहिए। मोदी ने आठ-नौ जुलाई को रूस की यात्रा की थी और अमेरिका ने इसकी आलोचना की थी। ऐसी खबरें हैं कि मोदी की रूस यात्रा को लेकर कई पश्चिमी देश नाखुश हैं।

भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा पर अमेरिका की चिंताओं को गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि बहुध्रुवीय विश्व में सभी देशों को अपनी ''पसंद को तरजीह देने की स्वतंत्रता'' है और सभी को ऐसी वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 फाइनल मैच आज

नईदिल्ली। मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखकर श्रीलंका के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले फाइनल में जीत दर्ज करके रिकॉर्ड आठवां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। उसने लीग चरण में पाकिस्तान को सात विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से और नेपाल को 82 रन से हराया था। सेमीफाइनल में उसने बांग्लादेश को 10 विकेट से पराजित किया था।

भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक अपनी प्रतिद्वंद्वी टीमों को कोई मौका नहीं दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है लेकिन टीम प्रबंधन गेंदबाजों विशेषकर दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के प्रदर्शन से काफी खुश होगा।

दीप्ति ने टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक 9 विकेट लिए हैं जबकि रेणुका सात विकेट लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों का इकोनॉमी रेट भी शानदार है जिसका मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। इन दोनों की कसी गेंदबाजी का फायदा भारत के अन्य गेंदबाजों को भी मिला है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव इसका उदाहरण है जिन्होंने अभी तक 5.5 के इकोनॉमी रेट से 6 विकेट लिए हैं। भारतीय टीम के लिए कोई विभाग चिंता का विषय नहीं है लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स को बल्लेबाजी के कम मौके मिलने से वह थोड़ा चिंतित हो सकता है। दूसरी तरफ श्रीलंका भी अभी तक अजेय रहा है। उसने टूर्नामेंट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है। श्रीलंका ने ग्रुप चरण में मलेशिया को 144 रन से हराया था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

आईसीआईसीआई बैंक का जून तिमाही में 10% बढ़ा मुनाफा

नईदिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया। बैंक का कंसॉलिडेटिड नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में 9.96 प्रतिशत बढ़कर 11,695.84 करोड़ रुपये हो गया। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक के 10,636.12 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। देश में दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ने शनिवार रेगुलेटरी फाईलिंग में बताया कि स्टैंडअलोन आधार पर उसका मुनाफा जून तिमाही में 14.62 प्रतिशत वृद्धि के साथ 11,059 करोड़ रुपये रहा, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,648.2 करोड़ रुपये था। बैंक की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 45,998 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 38,763 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा बैंक का खर्च जून तिमाही में बढ़कर 29,973 करोड़ रुपये हो गया।

दो अगस्त को खुल सकता है ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ

नईदिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देसी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए दो अगस्त, 2024 को खुल सकता है। ओला इलेक्ट्रिक ने ताजा इश्यू और ओएफएस के जरिये करीब 74 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बीच, ओला इलेक्ट्रिक 1 अगस्त को अपने आईपीओ के लिए एंकर राउंड शुरू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 से 6 अगस्त के बीच आम लोगों के लिए खुलने की संभावना है। ईवी कंपनी का आईपीओ 9 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही आईपीओ लाने वाली यह पहली भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी बन जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक ने ताजा इश्यू और ओएफएस के जरिये करीब 74 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है।

भारत की सॉवरिन रेटिंग घटने के आसार कम : एसएंडपी

नईदिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि उसे भारत की सॉवरिन रेटिंग घटाए जाने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जब तक कि भारत की राजकोषीय स्थिति में कोई गंभीर गिरावट नहीं आती है, तब तक ऐसा नहीं होगा। साल के मध्य में आए एशिया प्रशांत सॉवरिन रेटिंग पर अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा, 'हमारे राजकोषीय और ऋण संबंधी आकलन फिलहाल भारत पर हमारी रेटिंग के लिए कमजोर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जब तक राजकोषीय स्थिति में कोई गंभीर गिरावट नहीं आती है, हमें नहीं लगता कि भारत की सॉवरिन रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे गिरेगी।' एसऐंडपी ने कहा कि हाल के संसदीय चुनाव के परिणामों से भारत के राजकोषीय सुधारों पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ने के आसार नहीं है। इसमें कहा गया है, 'देश का कर राजस्व 10 साल से ज्यादा के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में अब तक के सर्वोच्च स्तर 670.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण कुल भंडार में बढ़ोतरी हुई है। यह सप्ताह के दौरान 2.57 अरब डॉलर बढ़कर 588.05 अरब डॉलर हो गया है। इसके पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 9.69 अरब डॉलर बढ़कर 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 666.85 अरब डॉलर था। सोने का भंडार 1.32 अरब डॉलर बढ़कर 59.99 अरब डॉलर हो गया है, जबकि आईएमएफ में रिजर्व की स्थिति बगैर किसी बदलाव के 4.60 अरब डॉलर रही है। एसडीआर में 9.5 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और 18.20 अरब डॉलर हो गया है।

रोजगार और विकास का बजट

अवधेश कुमार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024 -25 के बजट पर आम प्रतिक्रियाएं अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं। हालांकि सामान्य दृष्टि से भी देखें तो यह बजट ऐसा है जिसमें विपक्ष को तीखी आलोचनाओं के लिए ठोस आधार प्राप्त नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के पूर्व से लेकर अभी तक विपक्ष ने इस सरकार पर युवाओं, किसानों ,गरीबों को नजरअंदाज करने तथा बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। इस बजट का आरंभ ही युवाओं और रोजगार सृजन से हुआ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके संदर्भ में अंतरिम बजट में काफी प्रावधान किए गए थे। यह बजट उसी का विस्तारित रूप है। बजट को समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है।

यह एक साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने, स्वरोजगार सृजन पर बल देने, भारत की विरासत तीर्थ और पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा सबके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विस्तार पर फोकस करने वाला बजट है। यह बजट फिर एक बार बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का भारत को लेकर सपना क्या हैं। उन्होंने पहले भी अपने भाषणों तथा पिछले सारे बजटों में वैसे भारत की रूप-रेखा प्रस्तुत की है जो वर्तमान अर्थव्यवस्था के मानदंड में विश्व के शीर्ष देशों की कतार में हो, जहां लोगों को जीविकोपार्जन के साधन हों, स्किल से भरे युवाओं तथा समाज का हर वर्ग युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग व कारोबारी सबके बीच संतुलन भी हो। किंतु इन सबके साथ भारत अपने अध्यात्म,

सभ्यता, संस्कृति और विरासत की मूल पहचान के साथ विकसित भारत बने। इस बजट में इन सपनों का समग्रता से समावेश है लेकिन इसका मुख्य यू.एस.पी. रोजगार है।

आप देखेंगे कि 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां-जहां सबसे ज्यादा फोक्स करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पी.एम. मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 3000 नए आई.टी.आई., 7 आई.आई.टी., 16 आई.आई.आई.टी., 7 आई.आई.एम., 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। वस्तुत: नैशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख ही है। नौकरी की संख्या बढने के बावजूद काफी युवा वंचित हैं तो इसका कारण स्किल के मापदंड पर खरा नहीं उतरना है। तक हम स्किल के मापदंडओं पर काफी पीछे हैं। इस दृष्टि से बजट में युवाओं की इंटर्नशिप की एक ऐसी विशिष्ट योजना है जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं गया था। एक करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में शीर्ष-500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना इस बजट का प्रमुख आकर्षण है। सीधे काम करते हुए स्किल विकास की ऐसी योजना पहले नहीं आई थी। इसमें इंटर्नशिप करने आए युवाओं तथा कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं दिया गया है। युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपए का भत्ता तथा एकमुश्त मदद के रूप में 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करनी होगी।कॉरपोरेट अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि खर्च करते हैं। उन्हें उसी में से प्रदान करना है। इस तरह यह पूरी तरह व्यावहारिक है। कल्पना करिए अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में भारत कैसे स्किल वाले युवाओं का देश बन जाएगा।

छत्तीसगढ़ के दो जिलों को जल्द मिलेगी खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृतिः मांडविया

केन्द्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया सेंटर में दिए जा रहे खेल सुविधाओं और श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो जिलो में जल्द ही खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया सेंटरों में अधोसंरचना निर्माण के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। केन्द्रीय खेल मंत्री न्यू सर्किट हाउस में खेल एवं श्रम विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री किरण देव सिंह, श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। दो जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ हो जाएंगे। इससे राज्य के खेल प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा। इन सेंटरों में 1181 खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। राज्य में स्थापित उद्योगों से खेलों के लिए सीएसआर मद से राशि उपलब्ध कराने के प्रयास किया जाए। खेलो इंडिया के तहत राज्य में स्थापित सभी सेंटरों में खेलों के लिए आवश्यक सभी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाए जाएं। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए औषधालयों में आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञों के साथ-साथ आवश्यक दवाईयों का भण्डारण पर्याप्त रूप से हो। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएं। श्रमिकों के लिए आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ सिकलसेल के परीक्षण एवं उपचार की भी व्यवस्था की जाए।

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने राज्य में खेलों के विकास के लिए स्कूल स्तर से ही बच्चों को सुविधाएं और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि खेल मैदान में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाओं के साथ-साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। श्रम विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. ने अवगत कराया कि राज्य के श्रमिकों का पंजीयन कर श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्यों में प्रवासी संसाधन केन्द्र अर्थात मोर चिन्हारी भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर सहयोग मिल सकेगा। इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव श्री तारन प्रकाश सिन्हा,,खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे जोन 6 के जनसमस्या निवारण शिविर में

रायपुर। जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर के पहले दिन जोन-6 के शिविर में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। सांसद श्री अग्रवाल ने शिविर के अलग-अलग विभागों के स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली और पीएम पीएम सौर घर योजना का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को दिलाने को कहा। सांसद श्री अग्रवाल ने अन्य विभागों के स्टॉल में पहुंचकर जानकारी ली।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर ने रायपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर ने नया रायपुर स्थित विश्राम गृह में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान, श्रीमती ठाकुर ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि अधिकारी जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति का नियमित निरीक्षण करें और महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए हरसंभव मदद करें। उन्होंने कहा कि हमारे देश का भविष्य बच्चों और महिलाओं के हाथ में है, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना होगा। बैठक में महतारी वंदन योजना, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, बाल संरक्षण योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्रीमती ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं और उन्हें योजना के लाभ से अवगत कराएं। ।

इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और उनकी अद्यतन प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में संचालक, महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता के हक की रक्षा के लिये कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है -बैज

मानसून सत्र में हमने जनता की समस्याओं पर सरकार को घेराः महंत

भाजपा सरकार के 7 महीने में राज्य के हालात हुये बदतरः भूपेश बघेल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण पत्रकारवार्ता हुई। पत्रकार वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि पिछले पांच दिन राज्य की राजनीति के लिये तथा राज्य की जनता के लिये महत्वपूर्ण रहे। 22 जुलाई से राज्य की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ जो कल ही समाप्त हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज्य की जनता के हक की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ा। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं के अधिकारों को हमारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर सरकार को आईना दिखाया। जनता की आवाज को बुलंद करने के लिये कांग्रेस पार्टी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव किया। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था रोज-रोज हो रही लूट, डकैती, बलात्कार, हत्याओं की घटनाओं से प्रदेश में एक डर का माहौल बन गया है। हमारे विधानसभा घेराव के बाद जनता में एक भरोसा पैदा हुआ कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिये मजबूत विपक्ष है। विधानसभा घेराव में बरसते पानी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुये।

सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी से इतना ज्यादा घबराई हुई थी, पूरी राजधानी को सील कर दिया गया था। हमारे हजारों साथियों को रास्ते में रोक दिया गया। बिलासपुर की ओर से आने वालों को धरसींवा में रोक दिया गया, उनके वाहनों को किनारे खड़ा करवा दिया गया। महासमुंद की ओर से आने वालों को महासमुंद में रोक दिया गया। जगदलपुर, धमतरी से आने वालों को अभनपुर में रोका गया। राजनांदगांव, दुर्ग से आने वालों को कुम्हारी से आगे नहीं आने दिया गया। राजधानी में वाहनों की पार्किंग कार्यक्रम स्थल से 10 कि.मी. दूर बनाया गया था ताकि कम से कम लोग घेराव स्थल मंडी गेट तक पहुंच सकें। सरकार के तमाम अवरोध और बरसते पानी के बावजूद हमारा कार्यक्रम सफल रहा। हजारों साथियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से प्रहार किया। हमारे अनेकों साथी घायल भी हुये, लेकिन इस दमन से हमारा हौसला और मजबूत हुआ। हम मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ जनता के हित में अपना संघर्ष इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने तक जारी रखेंगे।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि 5 दिन में 4 स्थगन पर चर्चा कराने को सरकार को बाध्य किया, यह हमारी बड़ी सफलता है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था पर चर्चा किया। जनता की समस्याओं को तथ्यपूर्ण प्रस्तुत किया। बलौदाबाजार की घटना जिससे पूरा देश कलंकित हुआ इसमें भी हमने सरकार को घेरा। किसानों की समस्या को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभावी ढंग से उठाया। बिजली, खाद की कमी, मलेरिया, डायरिया से हो रही मौतों पर हमने सरकार को आईना दिखाया। हमारी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार के कामों को सरकार ने बंद कर दिया। अस्पतालों में एिएजेंट नहीं है ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है। कमीशन खोरी से दवाये भी नहीं बची है। नक्सली घटना पर हमने जब सच्चाई बताया कि थानों में जब्त भरमार बंदूकों को सरकार ग्रामीणों के शवों को साथ रखकर नक्सली बताती है। मैंने सरकार से पूछा कि जप्त भरमार बंदूको की जांच कब कराई? हमने सशक्त भूमिका निभाया। हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिये समर्पित दल कांग्रेस के सदस्य है। पूरे सत्र के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या सहित अन्य निम्नानुसार ज्वलंत मुद्दों स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचना एवं प्रश्नों के माध्यम से जनता का पक्ष रखते हुए सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

सावन की पहली बारिश में लबालब हुआ गंगरेल डैम

रायपुर। सावन की पहली ही बारिश में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डैम यानी गंगरेल डैम पानी से लबालब है। 32 टीएमसी की क्षमता वाले इस बांध में अब तक लगभग 18 टीएमसी पानी भर चुका है। अब तक रिकॉर्ड 8 हजार 713 क्यूसेक पानी की आवक हुआ है। हालांकि इस बांध की प्यास अभी तक पूरी तरह से नहीं बुझी है। बांध में अभी भी करीब 50 प्रतिशत पानी भरा है, जिसमें से लगभग 35 प्रतिशत ही उपयोगी पानी का भराव हुआ है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध कहे जाने वाला गंगरेल बांध हफ्तेभर से हो रही बारिश के चलते अब जल भराव की स्थिति सामान्य हुई है। लगभग 32 टीएमसी की क्षमता वाले इस बांध में करीब 18 टीएमसी पानी भराव हो चुका है, जो कि कुछ दिनों पूर्व सूखने की हालत में था। वहीं 1 जून से जिले में हुई बारिश के आंकड़े के मुताबिक जिले में एक जून से अब तक 556.1 मिलीमीटर से ज्यादा औसत वर्षा दर्ज की गई है। धमतरी तहसील में 533.1 मिलीमीटर, कुरूद तहसील में 457.9 मिलीमीटर, मगरलोड में 433.3 मिमी, नगरी तहसील में 747.8 मिमी, भखारा में 437.2 मिमी, कुकरेल तहसील में 584.2 मिमी और बेलरगांव तहसील में 698.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज

कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. नवागढ़ तहसील के कुआं गांव में कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत हो गई है. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना पर पुलिस और नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों युवक पंप निकालने के कुएं में उतरे थे, तभी यह हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार कुआं गांव में दो युवक पंप निकालने के लिए कुएं में उतरे थे. इस दौरान दोनों कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए. उन्हें बेहोश देख तीसरा युवक भी उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरा और वह भी बेहोश हो गया. जिससे तीनों की कुएं में ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

कैग रिपोर्टः कांग्रेस कार्यकाल में हुई है गड़बड़ीः जायसवाल

रायपुर। कैग की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपनी प्रति?क्रिया व्यक्त की है. कैग की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है. तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा? कि रिपोर्ट पुरानी होगी, उस समय कोरोना काल था. सीएजी की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आना एक सतत प्रक्रिया है. 2016 से 2022 तक की सीएजी की रिपोर्ट आई है. अगर कांग्रेस नेता कहते हैं कि रिपोर्ट में गड़बड़ी है तो सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस कार्यकाल की रिपोर्ट है. राज्य में कई विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टॉर की कमी है. लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि कुछ विशेष उपकरण की खरीदी में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी. उसकी जांच पहले से चल रही है. सीएजी की रिपोर्ट से विभाग को जांच में सहूलियत मिलेगी. सीएजी की रिपोर्ट में जिन अनियमितता की बात होगी, उसके माध्यम से जांच आगे बढ़ाई जाएगी. सीएजी की रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पुरानी होगी. उस समय कोरोना काल से गुजरना पड़ा था. सरकार ने सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे. हमारे जमाने में मलेरिया और डायरिया के उन्मूलन के लिए जो काम हुए हैं.

लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम पर आयोजित हुई कार्यशाला

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर में शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (द पब्लिक एक्जामिनेशन, प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीस, एक्ट 2024) पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये कानून के प्रावधानों के संदर्भ में आयोग के पैनल अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कानून के संबंध में व्याख्यान दिया गया। विदित हो कि उक्त कानून 21 जून 2024 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके तारतम्य में उत्तरप्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा भी इस कानून को राज्य की परीक्षाओं में लागू करने का अध्यादेश पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यशाला में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण वर्मा, सदस्य डॉ. सरिता उइके, सदस्य श्री संतकुमार नेताम एवं आयोग के सचिव श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, विधिक सलाहकार श्री सुधीर कुमार, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती लीना कोसम एवं विधि अधिकारी श्री अपूर्व श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने किया अनुभूति केन्द्र का उद्घाटन

रायपुर। अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मप्र व छग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास रहे। इस दौरान उन्होंने प्रथम दिन, शुक्रवार को कोअपर के.भ.नि.आयुक्त, श्री वी. रंगनाथ ने क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के कार्य निष्पादन, कार्य प्रणाली, उपलब्धियों व चुनौतियों की समीक्षा की। इस अवसर पर कार्यालय के प्रभारी श्री अभिषेक कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - 1 ने जानकारी दी कि वर्तमान में कार्यालय द्वारा उच्च वेतन दर पर पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरणों तथा मृत्यु दावों के निपटान को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। शनिवार को अपर केद्रिन्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कार्यालय में भविष्य निधि सदस्यों व पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिआधुनिक व तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित नवीन अनुभूति केन्द्र का उद्घाटन किया। जहाँ अंशधारकों को विभिन्न आनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसमें भविष्य निधि दावों, अग्रिम दावों, अंतरण दावों, संयुक्त घोषणापत्र, जीवन प्रमाणपत्र को आनलाइन भरा जाना इत्यादि। साथ ही कार्यालय में आने वाले समस्त आगंतुकों हेतु सहजता से जानकारी प्रदान किए जाने हेतु नवीन कियोस्क स्थापित किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

धर्म करना तो बहुत दूर की बात है, आज हर काम के लिए लोगों के पास बहाने है

रायपुर। दादाबाड़ी में आत्मस्पर्शी चातुर्मास 2024 के आठवें दिन शनिवार को दीर्घ तपस्वी श्री विरागमुनि जी ने कहा कि किसी काम को नहीं करने के लिए आप सौ बहाने बना सकते हो और जो काम आपको करना होता है, उसके लिए तो आप कभी बहाना नहीं बनाते। दुकान जाने, ऑफिस जाने के लिए आप बहाने नहीं बनाते है। वहीं, अगर आपको मंदिर जाना हो या फिर कोई मेहमान घर आए तो आप दुकान और ऑफिस का बहाना बनाकर निकल जाते हो।

उन्होंने कहा कि लोगों के पास हर एक बात के लिए बहाना होता है। परन्तु किसी को अपने दुकान जाना हो तो क्या वह बहाना करता है। भले ही नौकर बहाना करें पर मालिक कभी नहीं कर सकता। मंदिर जाने के लिए, भी लोग घरवालों से कहते है कि मेरे तरफ से भी आप लोग मंदिर चले जाना। बहाना हमारे पास हर समय तैयार होता है। जबकि परमात्मा कहते है कि कोई भी अगर अच्छा काम है, तो कोई बहाना मत ढूंढो। बल्कि उसे काम को करने का बहाना बनाओ और वह काम कर जाओ। उन्होंने आगे कहा कि भगवान तो हमारे अंदर है, तो हम मंदिर क्यों जाते है। जब आप मंदिर जाते हो तो वहां कोई पाप नहीं करते जबकि मंदिर से निकलते ही आप पाप करना शुरु कर देते हो। आप यह सोचते हो कि भगवान तो मंदिर के चार दीवारों के बीच ही हैं। इसके बाहर कोई देखने वाला नहीं तो खुलकर पाप करो। जबकि भगवान सब जगह है। सबके अंदर भगवान है। भगवान का केवल ज्ञान इतना व्यापक है कि कोई चीज उनसे अछूती नहीं है, कुछ भी उनसे दूर नहीं है, उनके केवल ज्ञान से हर चीज स्पष्ट है।

हम सिर्फ अपने आगे कि ओर ही देख सकते है। अगर आप आसपास नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाते हो, तो वह खराब हो सकता है, पर भगवान का सीसीटीवी कभी फ्यूज नहीं होता और उसकी रेंज भी कम नहीं होती। तो आप कभी मत सोचना कि भगवान केवल मंदिर में है, उनकी दृष्टि सब जगह है। उन्हें आंखों की जरूरत नहीं है। हर जगह परमात्मा है। जो वैभव, जो गुण भगवान के पास है, वही वैभव और गुण सबके पास है। बस फर्क यह है कि हमारे अंदर जो अनंत गुण है, उस पर हमने परदा लगा रखा है। उसे इतना ढंक दिया कि आपको यह पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर भी कुछ है। आप सोचते है कि जब समय आएगा तो उसका उपयोग करेंगे। जबकि आपको हर समय इन्हें उपयोग करते रहना है। उन्होंने आगे कहा कि आप अपने आप से कहो कि मैं आत्मा हूं। जितने बार आप यह बोलोगे आप खुद के अंदर जाते जाओगे।

रायपुर केन्द्रीय जेल में अध्यात्म के माध्यम से बंदियों के मनोदशा में सुधार के प्रयास

रायपुर। रायपुर स्थित केंद्रीय जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु लगभग 60 बंदियों की रामायण मंडली बनाई गई है। मंडली द्वारा विभिन्न बैरकों में प्रत्येक त्यौहारों के अवसर पर रामायण का पाठ तथा प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा तथा प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। रामायण मंडली के मुख्य गायक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी बोधन पिता रघुनाथ ने बताया कि वह जब भी पेरोल पर घर जाता है। वह गांव में रामायण मंडली में शामिल होता है तो उसके गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते है और कहते है कि, जेल एक जेल न रहकर सुधारगृह में परिवर्तित हो गया है। गांव वाले भी उससे बोलते हैं कि इतना अच्छा रामायण आप जेल में रहकर सीख लिये हो यह तो अद्भुत है। उसने अपने गांव दियागढ़ थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ में भी रामायण मंडली का गठन किया है। इसी प्रकार प्रतिदिन गीता सीखने वाले व रामायण के टीका करने वाले आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी चक्रधर पिता बंशीधर ने बताया कि वह प्रतिदिन आध्यात्म ही उसके जीवन का आधार है, वह परमात्मा को अपना सब कुछ सौंप चुका है। प्रतिदिन सीखे गीता के श्लोकों का पाठ, उसके अर्थ की चर्चा अपने बैरक के अन्य साथी बंदियों के साथ करता है। वह अन्य बंदियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। गांव जाने पर उसके गांव वाले उससे गीता, रामायण, पुराणों के बारे में चर्चा करते है तो उसका शुद्ध उच्चारण सुनकर कहते है कि आप जेल जैसी जगह में भी रहकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिये हो। उनका कहना है कि वो प्रतिदिन अपने साथी बंदी दोणाचार्य, धरम, वासुदेव के साथ पाठ कर आनंदित रहता हूं तथा अपनी सजा अच्छे से काट रहा हूं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.